सोशल मीडिया से जुड़ें
NewsTransportVishesh
YouTube
Digital Edition

न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

वर्ष 1, अंक 118, नई दिल्ली, बुधवार, 24 फरवरी 2023, पेज 8

NEWS NTV TRANSPORT VISHESH
www.newstransportvishesh.com
सबसे तेज, सबसे पहले
आपको पहुंचाये
परिवहन क्षेत्र की सभी जानकारियां
09212122095
09811732095

03 पार्षद रेखा गुप्ता और अमित नागपाल पर होगी कार्रवाई
05 मारुति और हुंडई की इन कारों के लिए सेट हो चुका है स्टेज
08 दुनिया के मंच पर न्यू इंडिया की बुलंद आवाज हैं एस जयशंकर

आज का सुविचार

छोटी चीजों में बारे हमेशा वफादार रहिये क्योंकि इन्ही में आपकी शक्ति निहित होती है।

इनसाइड

डिपो गेट पर बस की स्टेयरिंग फेल, सहायक मैकेनिक सस्पेंड

रायबरेली। परिवहन निगम के रायबरेली डिपो की कार्यशाला में मरम्मत होने के बाद 10 मीटर भी बस नहीं चल सकी। कार्यशाला के गेट के पहले ही स्टेयरिंग फेल हो गई। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। बसों की मरम्मत में लापरवाही बरतने पर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने बुधवार को सहायक मैकेनिक को निलंबित कर दिया। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक एमएल केसरवानी ने बताया कि बुधवार को वाहन संख्या यूपी 15 एटी 3063 को कार्यशाला में मरम्मत के लिए दिया गया। मरम्मत का काम होने के बाद चालक बस को लेकर चला तो कार्यशाला के गेट पर ही बस की स्टेयरिंग फेल हो गई। इसके अलावा अन्य बसों में भी निर्देश के बाद भी मरम्मत का काम सहायक मैकेनिक ने ठीक से नहीं किया। उन्होंने बताया कि कर्मचारी ने ठीक से काम नहीं किया। कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वहन न करके निगम की छवि को धूमिल करने का काम किया। मामले में सहायक मैकेनिक ऋषिकेश को निलंबित करके विभागीय कार्रवाई के लिए जांच शुरू करा दी गई है। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

दिल्ली की सड़कों पर जल्द दौड़ेगी बाइक टैक्सी! सरकार कर रही राइड एग्रीगेटर नीति पर विचार

संजय बाटला

दिल्ली में जल्द ही एग्रीगेटर नीति लागू होने जा रही है। बगैर अनुमति के चल रही एप आधारित बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने इस नीति को जल्द जमीन पर उतारने के लिए परिवहन विभाग से कहा है।

नईदिल्ली। दिल्ली में जल्द ही एग्रीगेटर नीति लागू होने जा रही है। बगैर अनुमति के चल रही एप आधारित बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने इस नीति को जल्द जमीन पर उतारने के लिए परिवहन विभाग से कहा है। सरकार चाहती है कि इस नीति को लागू करके दुपहिया और कार टैक्सी को अपने दायरे में लाकर सरकार के नियमों के तहत इन्हें चलाने की अनुमति दी जा सके। इससे अवैध रूप से चल रही दुपहिया टैक्सी सेवा को बंद करने के बाद कानूनी तौर पर स्वीकृत दुपहिया टैक्सी सेवा को शुरू किया जा सके।

जानें इस नीति के बारे में सबकुछ

दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने की पहल करते हुए मोटर वाहन एग्रीगेटर्स स्कीम 2021 को लागू करने की तैयारी की है। सरकार का प्रयास था कि इस साल के शुरुआती महीनों में इसे लागू कर दिया जाए, मगर अवैध रूप से चल रही बाइक टैक्सी को बंद कर देने के बाद सरकार इस नीति को लेकर और गंभीर हो गई है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस नीति को जमीन पर उतारने के लिए कागजी कार्यवाही शीघ्र पूरी करने के लिए परिवहन विभाग से कहा है।

नीति के तहत जहां इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा, वहीं ओला-उबर जैसी कंपनियों पर नकेल भी कसी जा सकेगी। ऐसी कंपनियों से संबंधित चालक सवारियों से अधिक पैसा वसूलते हैं या ठीक से पेश नहीं आते हैं तो संबंधित चालकों और कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। कैलाश गहलोत ने बताया कि दिल्ली जल्द ही शहर में यात्री व माल की परिवहन और वितरण

सेवाएं प्रदान करने वाले एग्रीगेटर्स के लिए नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। वाहन बेड़े को 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।

नीति के तहत अब राइड एग्रीगेटर्स यानी ओला-उबर और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को अपने वाहनों के नए बेड़े में अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करना होगा। इस नीति के अनुसार, राइड एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवाओं (खाद्य वितरण, ई-कामर्स लाजिस्टिक्स प्रदाता व कोरियर) को अगले तीन महीने (अधिसूचना की तारीख से) में सभी नए दोपहिया वाहनों में से 10 प्रतिशत और सभी नए चार पहिया वाहनों में से पांच प्रतिशत वाहन इलेक्ट्रिक के सुनिश्चित करने होंगे। विभाग ने पहले इस नीति में दोपहिया के लिए वाहनों को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक में बदलने की छूट दी थी मगर अब विभाग की योजना है कि बाइक टैक्सी में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को ही शामिल किया जाएगा।

नीति की विशेषताएं-

- कम से कम 50 वाहनों (बसों को छोड़कर) वाले सभी एग्रीगेटर्स को परिवहन विभाग से वार्षिक, नवीनीकरण लाइसेंस लेना होगा।
- सभी चालक और उनके वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य होगा।
- एग्रीगेटर कंपनियां किराया वसूलने में मनमानी नहीं कर सकेंगी।
- एग्रीगेटर को सभी चालकों और वाहनों की रियल टाइम, ट्रिप रूट और पैनिक बटन की स्थिति की निगरानी के लिए चौबीसों घंटे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर संचालित करना होगा।
- एग्रीगेटर एक महीने में 15 प्रतिशत या इससे अधिक शिकायतों वाले ड्राइवरों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा।
- एक वर्ष की अवधि में 3.5 से कम रेटिंग वाले ड्राइवरों को प्रशिक्षण और सुधारात्मक उपाय करने होंगे।
- ऐसे ड्राइवरों के प्रदर्शन की निगरानी एग्रीगेटर और परिवहन विभाग द्वारा की जाएगी।
- प्रदर्शन सुधरता नहीं है तो परिवहन विभाग उनके वाहन बैज को समाप्त कर देगा।
- वाहन आठ वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए और उनमें एग्रीगेटर लोगो होना चाहिए।

परिवहन विभाग का शिकंजा: बाइक टैक्सी की तीन कंपनियों को नोटिस, सात दिन के अंदर मांगा जवाब

एनटीवी संवाददाता

परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा के मुताबिक, एप आधारित बाइक टैक्सी की बुकिंग पर लगातार नजर रखी जा रही है। अवैध तौर पर अगर बुकिंग लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नियमों की अनदेखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

नई दिल्ली। दिल्ली में अवैध रूप से चल रही बाइक टैक्सी पर परिवहन विभाग का शिकंजा और कसने लगा है। परिवहन विभाग की तरफ से जारी सार्वजनिक नोटिस के बाद तीन एग्रीगेटर कंपनियों (ओला, उबर और रैपिडो) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने तीनों कंपनियों से सात दिन के अंदर जवाब मांगा है। पिछले तीन दिनों के दौरान 50 से अधिक बाइक टैक्सी का चालान हो चुका है।

परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा के मुताबिक, एप आधारित बाइक टैक्सी की बुकिंग पर लगातार नजर रखी जा रही है। अवैध तौर पर अगर बुकिंग लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नियमों की अनदेखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। विभाग की सख्ती के बाद एप से बुकिंग लेने के बाद भी यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए दोपहिया वाहन चालकों के नहीं पहुंचने की वजह से दिल्ली-एनसीआर के शहरों में लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

दिल्ली की सड़कों पर चलने के लिए किसी भी एग्रीगेटर (किराये पर वाहनों का परिचालन करने वाली कंपनी) को ना तो परिवहन विभाग की तरफ लाइसेंस जारी किया गया है। बावजूद इसके सुरक्षा के लिए तय मानकों की अनदेखी करते हुए दिल्ली-एनसीआर में बाइक टैक्सी का वाणिज्यिक इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है।

इससे सफर करने वालों को कम किराया में गंतव्य तक पहुंचने का मौका जरूर मिला लेकिन किसी भी हादसा या अनहोनी होने की सूरत में होने पर जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं होने की वजह से किराये पर किसके इशारे पर अब तक दोपहिया वाहनों का वाणिज्यिक इस्तेमाल हो रहा था। एग्रीगेटर अगर सात दिनों के अंदर माकूल जवाब नहीं देते हैं तो उनपर एक-एक लाख का जुर्माना भी किया जाएगा।

होम डिलीवरी करने वालों पर भी सख्ती

होम डिलिवरी के लिए भी दोपहिया वाहनों का वाणिज्यिक इस्तेमाल किया जा रहा है। कई बार अधिक वजन के सामन लादकर बाइक को चलाया जा रहा है, लेकिन ना तो चालक और ना ही गलियों और सड़कों पर चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई।

परिवहन विभाग की सख्ती के बाद अब ऐसे वाहनों पर भी नजर रखी जा रही है ताकि नियमों की अनदेखी करने वालों पर शिकंजा कस सके। हालांकि इसके लिए एप से सामान की बुकिंग करने के बाद घरों तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करने में परिवहन विभाग को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

बुकिंग के बाद भी लोग करते रहे इंतजार

बाइक टैक्सी की बुकिंग के बाद भी यात्रियों को वाहनों के पहुंचने के लिए इंतजार करना पड़ा। कार्रवाई के डर से वाहन चालकों के नहीं पहुंचने की वजह से लोगों को कैब, ऑटो या मेट्रो का सहारा लेना पड़ा। इस वजह से यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में सुबह और शाम के वक्त देरी हुई। बाइक टैक्सी का परिचालन बंद होने की वजह से दिल्लीवासियों को यात्रा पर पहले की अपेक्षा अधिक खर्च के बाद भी मुश्किलें पेश आईं।

जिले में संचालित हो रहे बिना नंबर वाले 21 हजार ट्रैक्टर

एनटीवी संवाददाता

बस्ती। जिले में बिना नंबर के चल रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली सुरक्षित यातायात के लिए खतरा बने हुए हैं। इसके बावजूद परिवहन विभाग इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि फोरलेन से लेकर अन्य मार्गों पर आए दिन ऐसी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां निर्माण सामग्री और अन्य सामान ढोते नजर आते हैं। परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार यहां 21 हजार से अधिक वाहनों से नंबर प्लेट गायब है। इनके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।

जिले में 29 हजार 539 ट्रैक्टर-ट्रॉली कृषि कार्य के लिए पंजीकृत हैं। इनमें तकरीबन 70 फीसदी (लगभग 21 हजार) की नंबर प्लेट गायब है। यही

नहीं कुछ ट्रैक्टरों पर तो सिर्फ जिले का कोड लिखकर काम चलाया जा रहा है। खेत से लेकर बाजार तक यह ट्रैक्टर व्यावसायिक उपयोग के लिए चल रहे हैं। इन पर न तो प्रशिक्षित चालक हैं, और न ही इनकी फिटनेस की कोई गाइड लाइन विभाग के पास है। कारण यह है कि सभी ट्रैक्टर का पंजीकरण सिर्फ कृषि कार्य के लिए जारी हुआ है, जिनकी फिटनेस की कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है। भट्ठों से लेकर मिट्टी व गिट्टी ढोने वाले इन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में कई तो ऐसे हैं जो एक ही वाहन स्वामी के लिए ढुलाई करते हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई से बचे हुए हैं। इस तरह के ट्रैक्टर ग्रामीण क्षेत्रों की बाजारों व सरयू नदी के बालू खदानों के घाटों के अलावा शहर के मूड़घाट व पटेल चौक के पास देखे जा सकते हैं।

बिना नंबर के ट्रैक्टर-ट्रालियों की होगी जांच, कार्रवाई

जल्द ही अभियान चलाया जाएगा और बिना नंबर व अवैध रूप से चल रहीं ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

-पंकज कुमार सिंह, एआरटीओ

डीएमआरसी अप्रैल से फीडर ई-बस दिल्ली सरकार को सौंपेगी: अधिकारी

एनटीवी संवाददाता

नयी दिल्ली। दिल्ली मेट्रो अप्रैल महीने से अपनी 100 फीडर ई-बसों का बेड़ा दिल्ली सरकार को सौंपना शुरू करेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, "डीएमआरसी इस साल अप्रैल महीने से सभी बसों को दिल्ली सरकार को सौंप देगी।" अधिकारी ने बताया कि ये 100 ई-बस दिल्ली मेट्रो की ओर से शहर में चल रहीं इलेक्ट्रिक बसों का पहला बेड़ा हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल, ये ई-बस शहर में छह मार्गों पर चल रही हैं। उन्होंने बताया कि फीडर बस दूरदराज के इलाकों तक सेवाएं प्रदान करेंगी जिनमें डीएमआरसी स्मार्ट कार्ड से भी भुगतान स्वीकार किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर के अंत

में, अधिकारियों ने कहा था कि दिल्ली सरकार जल्द ही दूर-दराज के इलाकों तक पहुंच मजबूत करने के लिए डीएमआरसी की इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े का अधिग्रहण करेगी।

इसके बाद, कैबिनेट ने हाल में डीएमआरसी की 100 से अधिक मौजूदा इलेक्ट्रिक बसों का अधिग्रहण करने का फैसला किया और वहीं, इस साल परिवहन विभाग के तहत अतिरिक्त 380 फीडर बसों का संचालन करने का फैसला भी किया गया।

दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा था, 'डीएमआरसी दिसंबर 2019 से शास्त्री पार्क और मजलिस पार्क डिपो से पूर्वी और उत्तरी क्लस्टर में फीडर ई-बसों का संचालन कर रही है। इन बसों को परिवहन विभाग द्वारा दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) के माध्यम से चलाया जाएगा।''

इसने कहा था, 'अतिरिक्त 380 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए, छह स्टेशन- वेलकम, कोहाट एन्क्लेव, रिठाला, नांगलोई, मुंडका और द्वारका की पहचान की गई है। इन स्थानों पर डिपो का निर्माण डीएमआरसी द्वारा किया जाएगा।'

अधिकारियों ने कहा था कि परिवहन विभाग फीडर बसों को प्रति किलोमीटर के आधार पर संचालित करेगा, जहां ऑपरेटरों को दिन के दौरान तय की गई दूरी के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

डिफेंस कॉरिडोर वाले शहरों के औद्योगिक क्षेत्रों को लेकर हुई घोषणा से अलीगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र जरूर लाभान्वित होंगे।

डिफेंस कॉरिडोर के सहारे उड़ान भरेगा तालानगरी का औद्योगिक ढांचा

एनटीवी ब्यूरो

प्रदेश सरकार ने बुधवार को अपना बजट पेश कर दिया है। सीधे तौर पर जिले को लाभ देने वाली कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, मगर डिफेंस कॉरिडोर वाले शहरों के औद्योगिक क्षेत्रों को लेकर हुई घोषणा से अलीगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र जरूर लाभान्वित होंगे।

बजट में जारी व्यवस्था के अनुसार, 550 करोड़ के बजट से डिफेंस कॉरिडोर में आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा और अलीगढ़ सहित संबंधित शहरों के औद्योगिक क्षेत्रों को डिफेंस कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। इससे शहर के छोटे उद्यमी और कारोबारी सीधे-सीधे लाभान्वित होंगे। बजट के जानकार लोगों से चर्चा के बाद जो तथ्य उजागर हुआ। उससे साफ है कि प्रदेश सरकार ने कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि व्यापार, उद्योग, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, नगरीय विकास, ग्राम्य विकास, सड़क-परिवहन आदि पर केंद्रित बजट पेश किया।

मगर जिले को लेकर सीधे तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई। सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को मिलने वाला है तो वे हैं शहर के लघु, मध्यम कारोबारी। शहर के औद्योगिक क्षेत्रों को डिफेंस कॉरिडोर से जोड़कर इनके आधार भूत ढांचे को मजबूत करने का जो प्रावधान किया है, वह आने वाले दिनों में अपने शहर के कारोबार और कारोबारियों के लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। इससे तालानगरी के उद्योग को और पंख लगेंगे।

उद्यमी बीमा योजना-प्लैज योजना से कारोबार और मजबूत : संयुक्त आयुक्त

उद्योग केंद्र के संयुक्त आयुक्त बीरेंद्र कुमार बताते हैं कि एमएसएमई को डिफेंस कॉरिडोर से जोड़ने की व्यवस्था के साथ प्रदेश सरकार ने दो बेहद महत्वाकांक्षी प्रस्ताव इस बजट में पेश किए हैं, जिसमें उद्यमी बीमा योजना शुरू की है, जो अब तक नहीं थी। इससे उद्यमी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा, प्लैज योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश में कम से कम 10 प्रस्तावों को पूरा करने

का लक्ष्य तय किया है। प्लैज योजना के तहत कोई भी कारोबारी अपनी भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर सकता है। इसके लिए सरकार की ओर से उसे सब्सिडी पर ऋण व अन्य संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। इस योजना के लागू होने से प्रदेश में औद्योगिक लैंड बैंक की कमी दूर होगी। इसके अलावा उद्योग, छोटे कारोबार व छोटी इकाइयों को ऋण योजनाओं, प्रोत्साहन योजनाओं में बजट बढ़ाया गया है। जो छोटे व्यापारियों-कारोबारियों के लिए लाभ कारी होगा। साथ में नए लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

इनसे लाभान्वित होगा जिला

धनीपुर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण काम जारी, जल्द उड़ान भरेंगे हवाई जहाज

यमुना एक्सप्रेसवे के सहारे फिल्म सिटी स्थापना से रोजगार व व्यापार बढ़ेगा

ब्लॉक से ब्लॉक मुख्यालय सड़क, एक जिला मार्ग सड़क चौड़ीकरण होगा

बजट से ये भी हैं संकेत

दाऊद खां से यमुना एक्सप्रेसवे आगरा तक चार लेन के भी हैं इसमें संकेत

दीनदयाल संयुक्त अस्पताल का उच्चीकरण हो सकता है बजट प्रस्ताव से

अलीगढ़-रामघाट कल्याण मार्ग का बजट पीडब्ल्यूडी कर सकता है जारी

इन योजनाओं से सीधे मिलेगा लाभ

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दुर्घटना बीमा योजना का लाभ

श्रमिकों के बच्चों को आर्थिक मदद एफडीआर के जरिए

पीएम आवास योजना का बजट बढ़ने से बनेंगे और मकान

कई पेंशन योजनाओं के जरिये गरीब, बुजुर्ग, विधवा लाभान्वित

मोबाइल-टेबलेट स्कीम के तहत युवा व छात्र भी लाभान्वित

श्रमिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण का भी जिले में लाभ

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड
कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट
कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

इनसाइड

महिलाएं हर दिन करें ये 3 योगासन, बिना जिम के मिलेगा स्लिम-ट्रिम लुक

एक्सरसाइज या योग करना सेहत के लिए फायदेमंद है. नियमित योग और एक्सरसाइज करने से कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है. इससे कई बीमारियों से निजात भी मिलती है. बिजी रहने की वजह से या घर से बाहर न जाने की आदत के चलते कई बार महिलाओं के लिए जिम या योग केंद्र जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है. कई बार महिलाएं चाहते हुए भी जिम नहीं जा पाती हैं और अपनी सेहत के साथ समझौता कर लेती हैं. हालांकि अगर आप चाहें तो घर में रहकर भी कुछ खास योगासन की मदद ले सकती हैं. जो आपको स्वस्थ रखने में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं.

यूपी के लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑर्थोपेडिक सर्जरी डिपार्टमेंट की क्लीनिकल योग इंस्ट्रक्टर डॉ. वंदना अवस्थी से उन योगासनों के बारे में जानते हैं, जो आपको स्वस्थ रखने के साथ कई बीमारियों से राहत देने में मदद करेंगे. वैसे तो कोई भी आसन सुबह के समय करना बेहतर होता है लेकिन समय न मिलने पर जब भी करें तो खाना खाने के बाद कम से कम दो घंटे का गैप जरूर रखें. इतना ही नहीं इन योगासनों को करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

चक्की चलनासन

इस योगासन को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर योगा मैट बिछाकर बैठ जायें. अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला कर मैक्सिमम गैप बनाएं. इस दौरान रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे. अब हाथों को जमीन पर एकदम सामने की ओर सीधा रखकर उंगलियों को आपस में फंसा लें. फिर अपने हाथों को क्लॉक वाइज यानी दायीं से बायीं तरह गोल-गोल उसी तरह से घुमायें जैसे चक्की चलाई जाती है. इसके बाद विपरीत दिशा में यही प्रक्रिया दोहराएं. इस योगासन को शुरू में एक-दो मिनट करें फिर धीरे-धीरे समय को बढ़ाएं. इस योगासन से पीसीओडी की दिक्कत में राहत मिलती है. जिससे अनियमित मासिक धर्म धीरे-धीरे नियमित होने लगता है साथ ही दर्द और ऐंठन से भी राहत मिलती है. इतना ही नहीं ये मेंटल स्ट्रेस को कम करने और मोटापे से निजात दिलाने में भी मदद करता है.

तितली आसन

तितली आसन करने के लिए योगा मैट पर सूर्य की ओर मुख कर के आराम की मुद्रा में बैठें. फिर अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला कर इस तरह से मोड़ें जिससे दोनों पैरों के तलवे आपस में मिल जायें. अब दोनों हाथों से पैर के तलवों को अच्छी तरह से पकड़ लें.अब तितली की तरह अपने पैरों को हिलाएं. इस आसन को भी शुरू में एक-दो मिनट करें फिर अपनी कैपिसिटी के अनुसार धीरे-धीरे इसका समय बढ़ाएं. तितली आसन करने से भी पीसीओडी की दिक्कत से राहत मिलती है. साथ ही पीठ का दर्द और मसल्स स्ट्रेस भी दूर होता है. इतना ही नहीं इस आसन को तीन महीने की गर्भावस्था के बाद भी किया जा सकता है. ये आसन डिलीवरी को आसान बनाने में भी मदद करता है. नियमित रूप से तितली आसन करने से ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है.

दंडासन

दंडासन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर बैठ जायें और पैरों को सामने की ओर फैला कर आपस में मिला लें. फिर दोनों हाथों को कंधों के बराबर अपनी जांघों के पास सीधा जमीन पर रखें.इस बीच रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें. अब दोनों पैरों के पंजो को अपनी ओर खींचें, कुछ सेकेंड रोक कर रखें फिर ढीला छोड़ दें. इस प्रक्रिया को दस से पंद्रह बार अपने सामर्थ्य के अनुसार दोहराएं. इस आसन को किसी भी आयु और अवस्था की महिलाएं आसानी से कर सकती हैं. दंडासन करने से कंधों में खिंचाव की दिक्कत कम होती है. रीढ़ की हड्डी लचीली और मजबूत होती है, मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और पाचन शक्ति बढ़ती है।

9 क्वालिटी को अपनाकर महिलाएं अंदर से बन सकती हैं खूबसूरत, दुनिया करेगी गर्व, खुद पर भी होगा नाज़

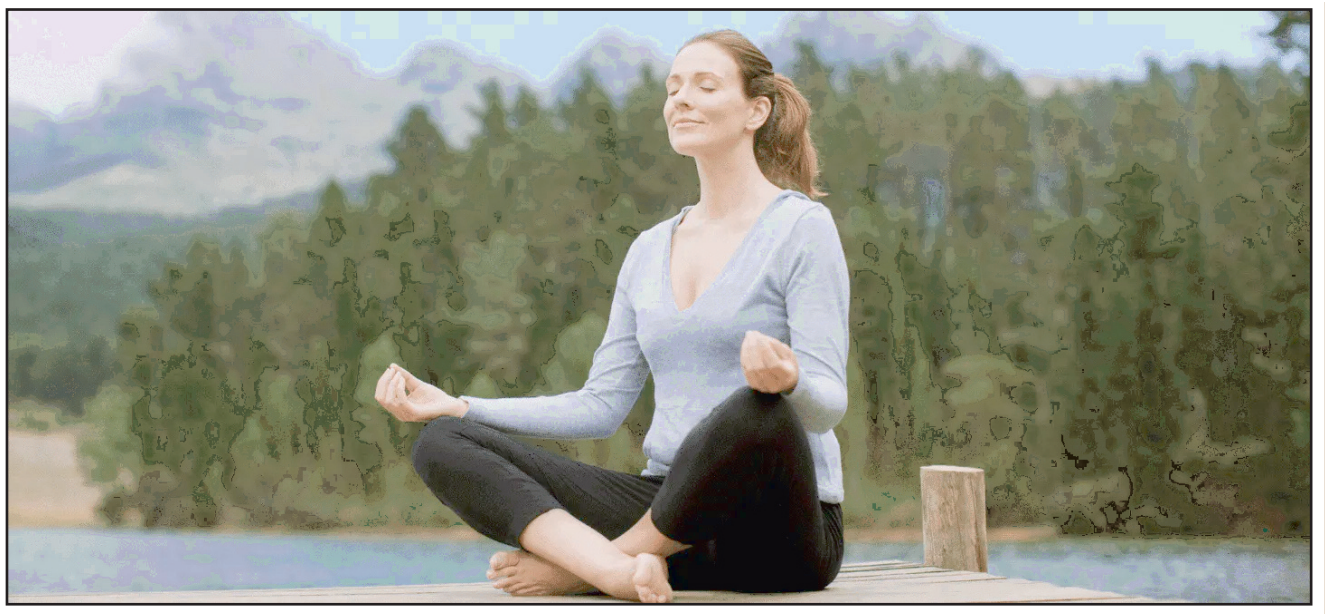

आमतौर पर जब बात खूबसूरती की आती है तो लोग नाक-नक्श और फिगर की बात करते हैं, लेकिन अगर आप दुनिया और अपनी नज़रों में खूबसूरत बनना चाहती हैं तो अंदर की खूबसूरती को निखारना ज़रूरी होता है.

जब बात महिलाओं की खूबसूरती की आती है तो लोग हजारों गुणों की बात करते हैं. ये गुण ज्यादातर समाज के बनाए गए मापदंडों के हिसाब से तय किए गए होते हैं. मसलन, लंबे बाल, तीखे नाक नक्श, पतले पैर आदि, लेकिन जब बात वास्तविक सुंदरता की आती है तो उसमें कुछ भी भौतिक नहीं होता. एक समय के बाद शारीरिक सुंदरता मिट जाती है, जबकि सच्ची खूबसूरती जीवनभर साथ रहती है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं इनर ब्यूटी की. आप अपने दिल से कितनी खूबसूरत हैं, ये बहुत मायने रखता है. अगर आप खुद की अंदरूनी खूबसूरती को निखारना चाहती है और खुद पर गर्व करना चाहती हैं तो अपने अंदर कुछ क्वालिटी को विकसित कर सकती हैं.

अंदरूनी खूबसूरती बढ़ाने वाली 9 क्वालिटीज

इंसानियत

अगर आप खुद से पहले दूसरों की सोचती हैं तो यह बताता है कि आपके अंदर कितनी इंसानियत है. ऐसे लोग भले ही मुसीबतों का सामना करते हैं, लेकिन उनके पीछे पूरी दुनिया खड़ी रहती है.

आत्मविश्वास

आत्मविश्वास आपकी पर्सनैलिटी को कई गुना निखार सकता है, इसलिए कुछ ऐसे काम सीखते रहें या करते रहें, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़े. याद रखें कि आत्मविश्वास और अहंकार के बीच बहुत पतली रेखा होती है.

इंटेलिजेंट

अगर आप इंटेलिजेंट हैं और आसानी से चीजों समझ लेती हैं तो ऐसी महिलाओं की तरफ लोग काफी आकर्षित होते हैं. ऐसे में अपनी स्मार्टनेस और ज्ञान का छिपाएं नहीं, बल्कि बढ़ाते रहें.

प्यार और दुलार

एक महिला होने के नाते अगर आपके मन में सभी के लिए प्यार या दुलार का भाव रहता है तो यकीन मानिए, आप हर दिल पर राज कर सकती हैं.

जिंदादिल

अगर आप लोगों के साथ काफी

गर्मजोशी में मिलती हैं और आपको लोगों के साथ अच्छा और खुशनुमा वक्त गुजारना आता है तो ऐसे लोगों के साथ सभी रहना पसंद करते हैं.

महत्वाकांक्षा

अगर आपके जीवन में कुछ करने की इच्छा है या जीने की कोई वजह है तो यह आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा. आप खुद को निखारने का हमेशा प्रयास करेंगी.

निःस्वार्थ भाव

अगर आप दूसरों की परवाह करती हैं और कई बार खुद को भूलकर उसकी मदद करने की कोशिश करती हैं तो ऐसे लोगों के साथ भला कौन रहना पसंद नही करता है. ऐसे लोगों की लोग इज्जत करते हैं.

धैर्य

हर अच्छी चीज को पूरा होने में वक्त लगता है. यह अगर आपकी भी सोच है तो यकीन मानिए कि आपके इस विचार की वजह से लोग आपकी काफी इज्जत करेंगे. आज के युग में धैर्यवान होना एक बहुत बड़ा गुण है जो सभी के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है.

भरोसेमंद होना

खुद के प्रति सच्चा होना जरूरी है. अगर आप खुद के लिए या अपनों के लिए वफादार हैं तो आपके साथ सभी रहना चाहेंगे और अपनी हर अच्छी बुरी बातों को आपके साथ शेयर करेंगे.

पुरुषों की तुलना में महिलाओं में हो जाती है इन विटामिंस की कमी, प्रेग नेंसी में दिक कत का ये भी है कारण

पुरुषों की तुलना में अक सर ये देखा जाता है कि महिलाओं में आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन डी, विटामिन बी12 जैसे जरूरी तत वों की कमी हो जाती है. अगर महिलाएं खुद की सेहत का ख याल रखें तो प्रेगनेंसी या मेनोपॉज के दौरान समस याओं से बच सकती है. आइए जानते हैं कि किन विटामिन की कमी महिलाओं में अक सर देखने को मिलती है.

अक सर महिलाओं की ये शिकायत रहती है कि रात भर सोने के बावजूद थकान महसूस करती हैं या उन हें हर वक त कमजोरी का अनुभव होता है. इन समस याओं को वे लंबे समय तक नजरअंदाज करती जाती हैं जो आगे चलकर बड़ी बीमारियों की वजह बन जाता है. अगर महिलाएं अपनी सेहत का ध यान रखें और शरीर में विटामिन स और मिनरल स की कमी की आपूर्ति के लिए हेल दी डाइट लें तो जीवन भर हेल दी जीवन जी सकती हैं.

वुमनहेल थ के मुताबिक, दरअसल, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर को विटामिन और खनिजों की आवश्यकता पड़ती है. हर विटामिन और मिनरल स के अपने अलग फायदे हैं जो शरीर के अलग अलग कामों को पूरा करने में मदद करते हैं. लेकिन कई वजहों से महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कुछ खास तरह के विटामिन और खनिजों की कमी पाई जाती है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को किन विटामिन की कमी हो जाती है और वे किस तरह इन हें पूरा कर सकती हैं.

फॉलिक एसिड या विटामिन बी9

फॉलिक एसिड शरीर में ब लड सेल स बनाने और डीएनए क्रिएट करने का काम करता है. यह भ्रूण के बेहतर विकास के लिए बहुत जरूरी है. इसकी कमी से प्रीमेच योर बर्थ या जन म के समय कम वजन होने का खतरा हो सकता है. ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाओं को रोजाना 400 से 800 एमसीजी फॉलिक एसिड डायटरी सेप लीमेंट के रूप में दिया जाता है. इसकी आपूर्ति के लिए आप हरी पत तेदार सब्जियां, फल, अनाज, नट्स, चिकन आदि का नियमित सेवन करें.

विटामिन बी12

विटामिन बी12 ब लड सेल स और ब्रेन न यूरॉन बनाने का काम करता है. यह भी प्रेगनेंसी में जरूरी होता है. इसके अलावा जो महिलाएं शाकाहारी हैं और जिनकी उम्र 50 से अधिक है उन हें विटामिन बी12 की कमी हो सकती है. इसके लिए आप मिल क, अंडा, चीज, चिकन, लीवर आदि डाइट में शामिल कर सकती हैं.

विटामिन डी

शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी जरूरी होता है. यह इम यूनिटी को भी बढ़ाता है. जबकि सूरज की रौशनी से स्किन का डायरेक ट संपर्क ना होने की वजह से महिलाओं में विटामिन डी की काफी कमी पाई जाती है. इसके लिए आप सेप लीमेंट का इस तेमाल कर सकती हैं.

कैल्शियम

लड़कियों को ग्रोइंग एज में जहां 1300 एमजी कैल्शियम की जरूरत होती है, वहीं मेनोपॉज के बाद 1200 एमजी कैल्शियम की जरूरत होती है. लेकिन अधिकतर मामलों में महिलाओं में इसकी कमी पूरी नहीं हो पाती. इसके लिए आप कैल्शियम रिच फूड का सेवन करें और सेप लीमेंट का सेवन करें.

आयरन

महिलाओं में आयरन की कमी की समस या भी काफी आम है. जिस वजह से उनके शरीर में ब लड सेल स की कमी हो जाती है और ऑक सीजन सप लाई सही तरीके से ना हो पाने के कारण कमजोरी, चक कर आना जैसी समस या होने लगती है. ऐसे में आप आयरन रिच चीजों को डाइट में शामिल करें.

इन चीजों से सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर

डाइटिशियन भी सर्दियों में घी, ड्राई फ्रूट्स, गुड़, अदरक, शकरकंद, गाजर, सरसों का साग और केसर जैसी चीजों को डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं. सर्दियों के दौरान ज्यादातर महिलाएं आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी ठंडी चीजें भी खाना पसंद करती हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि सर्दियों में ठंडी चीजें खाने से सेहत को कई नुकसान हो सकते हैं. आइए आपको बताते हैं सर्दी में ठंडी चीजों का सेवन करने के कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में.

पेट की प्रॉब्लम्स

हेल्थशॉट्स के अनुसार सर्दियों में ठंडा खाना खाने से आपको पेट से जुड़ी कई समस्याएं देखने को मिल सकती हैं. मसलन सर्दियों में ठंडी चीजों का सेवन करने से आपको पेट में सूजन, ऐंठन, पेट फूलना, थकान, बॉडी में शॉक महसूस होना और पाचन तंत्र वीक होने जैसी परेशानियां हो सकती हैं.

शरीर का तापमान कम होना

सर्दी के मौसम में बाहर का तापमान सामान्य से काफी नीचे चला जाता है. ऐसे में ठंडी चीजें खाने से आपकी बॉडी का टेंप्रेचर भी कम होने लगता है. जिससे ब्लड सर्कुलेशन पर बुरा असर पड़ता है और आपका खून जम भी सकता है.

गले में हो सकता है इंफेक्शन

जानकारों के अनुसार सर्दियों में ठंडा खाना खाने से आपको गले में थ्रोट इंफेक्शन हो सकता है. खासकर सर्दी के मौसम में कोल्ड कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडे जूस पीने से आपको गले में खुजली, जलन और इरिटेशन होने लगती है. ऐसे में गले का खास ख्याल रखने के लिए आप गर्म दूध, सूप, नट्स, मसाले और हर्ब्स का सेवन कर सकते हैं.

जुकाम होने का खतरा

सर्दी के मौसम में बॉडी काफी सेंसटिव हो जाती है. ऐसे में ठंडी चीजों का सेवन करना बीमारी को बुलावा देने जैसा होता है. बता दें कि सर्दियों के दौरान ठंडी चीजें खाने से आप खांसी, जुकाम, बुखार और सीजनल फ्लू जैसी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं.

पाचन पर पड़ेगा बुरा असर

सर्दियों में ठंडी चीजों का सेवन पाचन तंत्र को भी खासा प्रभावित करता है. दरअसल ठंडी चीजें काफी हैवी होती है. जिसे पचाने में आपको काफी दिक्कत आ सकती है.

महिलाएं 40 साल के बाद जरूर करें इन चीजों का सेवन, जोड़ों में नहीं होगा दर्द, हेल्दी रहने में मिलेगी मदद

बढ़ती उम्र के साथ सेहत का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है. खासकर महिलाओं में उम्र बढ़ने के साथ उनका एनर्जी लेवल भी कम होने लगता है. वहीं प्रॉपर हेल्थ केयर रूटीन फॉलो न करने पर महिलाएं कई गंभीर बीमारियों का भी शिकार हो सकती हैं. ऐसे में अगर आपकी उम्र 40 साल से अधिक है तो 5 सप्लीमेंट (Necessary supplements) को डाइट में शामिल करके आप हमेशा हेल्दी रह सकती हैं.

40 से अधिक उम्र वाली ज्यादातर महिलाओं के शरीर में पोषण की कमी देखने को मिलती है. जिसके चलते महिलाओं की मसल्स कमजोर होने लगती है. ऐसे में महिलाओं को कमर दर्द, घुटनों में दर्द या हड्डियों में दर्द की परेशानियां उठानी पड़ती हैं. हालांकि ओनली माई हेल्थ के अनुसार कुछ सप्लीमेंट्स को डाइट का हिस्सा बनाकर आप न सिर्फ बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी कर सकती हैं बल्कि 40 के बाद भी खुद को फिट और हेल्दी रख सकती हैं.

विटामिन बी 12

विटामिन बी 12 खाने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है और ब्रेन भी अच्छी तरह से फंक्शन करता है. इसके अलावा पेट की एसिडिटी से निजात पाने के लिए भी विटामिन बी 12 युक्त चीजें खाना बेस्ट होता है. ऐसे में महिलाएं अंडा, मछली और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी पूरी कर सकती हैं.

कैल्शियम

40 साल के बाद शरीर में कैल्शियम की कमी पर हड्डियां कमजोर होने लगती हैं. ऐसे में दूध और पनीर जैसी कैल्शियम रिच चीजों को डाइट में शामिल करके आप हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ-साथ दिल को हेल्दी और मसल्स को स्ट्रांग रख सकती हैं. मगर ध्यान रहे कैल्शियम युक्त चीजों का अधिक सेवन करने से आपको दिल की बीमारी भी हो सकती है. इसलिए कैल्शियम का सीमित

मात्रा में सेवन करना बेहतर रहता है.

मैग्नीशियम

मैग्नीशियम को मिनरल्स का बेस्ट सोर्स माना जाता है. ऐसे में मैग्नीशियम से भरपूर आहार लेने से शरीर का ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है. वहीं पाचन तंत्र को मजबूत बनाने और गैस या एसिडिटी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए भी मैग्नीशियम रिच चीजों का सेवन बेस्ट होता है.

विटामिन डी

शरीर में विटामिन डी की कमी होने से डायबिटीज, ब्रेस्ट कैंसर और दिल की बीमारी होने का खतरा रहता है. वहीं विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है. ऐसे में विटामिन डी का सेवन करने के लिए मछली, डेयरी प्रोडक्ट्स, अनाज और सीरियल्स को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

ओमेगा 3 फैटी एसिड

40 के बाद महिलाओं को दिल की बीमारी, जोड़ों में दर्द, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने और स्ट्रोक पड़ने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में ओमेगा 3 फैटी एसिड खाने से इन सभी बीमारियों का रिस्क कम हो जाता है. इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड को डाइट में एड करके आप कई गंभीर बीमारियों को भी मात दे सकती हैं.

दिल्ली MCD स्टैंडिंग कमेटी चुनाव: MCD की बैठक कल तक के लिए स्थगित, BJP पार्षद रेखा गुप्ता और अमित नागपाल पर होगी कार्रवाई

एनटीवी न्यूज

लगातार तीन बैठकों में हंगामा होने के बाद बुधवार को शांतिपूर्ण तरीके से मेयर का चुनाव तो हो गया, लेकिन स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव आम आदमी पार्टी (आप) और भाजपा के लिए चुनाव नाक की लड़ाई बन चुकी है। यही वजह है कि स्थायी समिति के छह सदस्यों के लिए चुनाव की प्रक्रिया देर रात तक जारी रही।

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के बाद अब स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव को लेकर एमसीडी सदन में रात से लेकर सुबह तक हंगामा जारी रहा। गुरुवार सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आप के पार्षद वोट कराने को लेकर नारेबाजी करने लगे। वहीं, भाजपा के पार्षद भी मेयर के आसन के सामने पहुंच गए। इसके बाद सदन की बैठक को शुक्रवार सुबह दस बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

इससे पहले हंगामे के बीच देर रात आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। इस बीच, हंगामे के चलते बैठक को कई बार स्थगित करना पड़ा।

पार्षदों की बीच हाथापाई, बोतलें फेंकी गई

बता दें कि जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होती है वैसे पार्षदों का हंगामा शुरू हो जाता है। कल रात पार्षदों के बीच हाथापाई हुई और बोतलें फेंकी गईं और आज सुबह से सदन में कागज के गोले फेंके गए। इस दौरान महिला पार्षद भी आपस में भिड़ती नजर आईं। फिर हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। भाजपा पार्षद स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव फिर से कराने की मांग पर अड़े रहे। हंगामे को लेकर एडिशनल डीसीपी शशांक जायसवाल ने सिविक सेंटर का दौरा किया।

सदन में नहीं हुआ मर्यादा का पालन- शैली

नवनिर्वाचित मेयर शैली ओबराय ने कहा कि सदन में मर्यादा का पालन नहीं हुआ है। पार्षदों पर हमला हुआ है। बीजेपी की रेखा गुप्ता ने पोडियम तोड़ा और अमित नागपाल ने बैलेट पेपर फाड़ा। इसलिए रेखा गुप्ता और अमित नागपाल पर कार्रवाई करेंगे।

कल सुबह 10 बजे तक बैठक स्थगित

एक घंटे स्थगित रहने के बाद हंगामे के बीच फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। वोट कराने के लेकर आप के पार्षद नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं, भाजपा के पार्षद भी महापौर के आसन के सामने पहुंचे। इसके बाद सदन की बैठक कल यानी शुक्रवार सुबह दस बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

नारेबाजी के बीच सदन की कार्यवाही फिर स्थगित

सदन में नारेबाजी के बीच एमसीडी सदन की कार्यवाही फिर से एक घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है।

स्थायी समिति का चुनाव तो होगा, सुप्रीम कोर्ट का है निर्देश

मेयर मेयर आसन के आगे आकर भाजपा पार्षद लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। जिस पर मेयर ने बार-बार पार्षदों को चेतावनी दी कि वह आज ही चुनाव कराकर रहेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आज ही चुनाव कराया जाना है। उनका कहना है कि किसी भी सूरत में आज ही चुनाव होकर रहेगा। वह बिना चुनाव के बैठक स्थगित नहीं करेंगी। उनका कहना था कि स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए 55 बैलेट बट चुके हैं। ऐसे में वह फिर से चुनाव नहीं करा सकती हैं।

तीन पदों पर जीतने की है भाजपा की कोशिश

इसलिए महत्वपूर्ण है नगर निगम की स्थायी समिति दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप ने छह पद पर चार प्रत्याशी उतार रखें हैं, जबकि भाजपा ने तीन प्रत्याशी उतार रखें है। भाजपा अगर सदन से तीन प्रत्याशी जीतती है तो वह स्थायी समिति के अध्यक्ष के लिए लड़ाई में आ जाएगी। इसलिए आप की कोशिश चार पदों को जीतने की है और भाजपा की कोशिश तीन पदों पर जीतने की है।

हार से बौखलाई भाजपा- AAP

आम आदमी पार्टी ने स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव में हो रहे हंगामे को भाजपा की बौखलाहट बताया है।

स्थायी समिति चुनाव में हार देख AAP ने किया हंगामा

भाजपा ने आरोप लगाया कि स्थायी समिति के चुनाव में हार देखकर आप के पार्षदों ने हंगामा किया। भाजपा पार्षदों पर हमला किया गया। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि आप का मेयर बनते ही निगम में तानाशाही शुरू हो गई है। स्थायी समिति के चुनाव में गुप्त मतदान के नियम का उल्लंघन किया गया। आप पार्षदों ने मतदान की तस्वीर दुर्गेश पाठक को भेजी।

प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि भाजपा को डर था कि आप स्थायी समिति का चुनाव नहीं होने देगी। इसलिए सीएम से मांग की गई थी कि वह आश्वस्त करें कि आप मेयर व उपमेयर के बाद स्थायी समिति का चुनाव होने देगी। भाजपा नेताओं ने कहा कि आप को स्थायी समिति के चुनाव में भी क्रास वोटिंग का डर है, इसलिए सोची समझी साजिश के तहत हंगामा किया गया।

भाजपा पार्षदों ने शैली ओबराय पर हमले की कोशिश की

आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मेयर का चुनाव हारने के बाद भाजपा के पार्षदों ने मेयर शैली ओबराय पर हमला करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक शैली ओबराय स्थायी समिति का चुनाव करा रही थीं। इसी दौरान उन पर हमला करने की कोशिश की गई। यह बात शैली ओबराय ने भी ट्वीट कर कही।

यह अस्वीकार्य - सीएम केजरीवाल

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह बिल्कुल चौंकाने वाला और अस्वीकार्य है। वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि भाजपा की न सिर्फ महिला पार्षदों ने, बल्कि पुरुष पार्षदों ने स्टेज पर जाकर शैली ओबराय पर हमला करने की कोशिश की। भाजपा को जनादेश स्वीकार करना होगा। उन्होंने कहा कि अपनी सरकार चोर दरवाजे से बनवाने की कोशिश मत करें।

तीन बैठकें रही असफल

इससे पहले लगातार तीन बैठकें बेनतीजा रही थीं। कांग्रेस ने चुनाव के बहिष्कार का एलान किया था। इसके बावजूद कांग्रेस की आया नगर की पार्षद शीतल चौधरी ने मतदान में हिस्सा लिया। शीतल चौधरी के पति वेदपाल ने बताया कि उनकी पत्नी ने मतदान में हिस्सा लिया। कांग्रेस के नौ पार्षदों में से आठ सदन में नहीं आए।

AAP की शैली ओबराय बनीं मेयर

ढाई माह तक राजनीतिक उठापटक और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में मेयर की लड़ाई आम आदमी पार्टी (आप) ने जीत ली है। निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में बुधवार को गहमागहमी के बीच हुए चुनाव में आप प्रत्याशी शैली ओबराय ने 34 मतों से जीत दर्ज की। उन्हें 150 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी रेखा गुप्ता के पक्ष में 116 वोट पड़े। वहीं, आप प्रत्याशी आले मोहम्मद इकबाल उपमेयर चुने गए।

AAP ने एमसीडी में भी गाड़ दिए झंडे

वर्ष 2012 में अस्तित्व में आने के बाद आखिरकार आप ने एमसीडी में भी झंडे गाड़ दिए हैं। वैसे, पिछले वर्ष सात दिसंबर को आया एमसीडी परिणाम आप के पक्ष में ही था। उसने 250 सीटों में 134 सीटें जीती थीं, लेकिन एलजी द्वारा मनोनीत सदस्यों के भी मेयर चुनाव में मतदान से मामला फंस गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो फैसला आप के पक्ष में आया।

निगम के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

निगम के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बुधवार शाम तक मेयर और उपमेयर चुन लिए गए, पर स्थायी समिति के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू होते ही हंगामा होने लगा।

पहले तू-तू, मैं-मैं, फिर मारपीट तक की नौबत आ गई। कुछ पार्षद टेबल के नीचे छिपे तो कुछ गेट के पीछे दुबक गए। कई पार्षद चोटिल भी हुए। भाजपा पार्षद अर्जुन मारवाह ने आरोप लगाया कि आप के पार्षदों ने उनकी पगड़ी पर हमला किया है।

इनसाइड

उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने एलजी को फिर लिखा पत्र, शिक्षकों को फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव पर मांगी मंजूरी

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक और पत्र लिखकर दिल्ली सरकार के स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी देने को कहा है।

नई दिल्ली। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को एलजी वीके सक्सेना को एक और पत्र लिखकर दिल्ली सरकार के स्कूली शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी देने को कहा है। सिसोदिया, जिनके पास दिल्ली सरकार में

फरवरी से पुस्तक मेला की होगी शुरुआत, शिक्षा मंत्री करेंगे उद्घाटन

Delhi World Book Fair 2023 दिल्ली के प्रगति मैदान के नव निर्मित हाल 234 में आयोजित किया जा रहा है। पुस्तक मेले की शुरुआत 25 फरवरी यानी शनिवार को होगी। मेले का उद्घाटन दोपहर ढाई बजे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे।

नई दिल्ली। इस बार पुस्तक मेला दिल्ली के प्रगति मैदान के नव निर्मित हाल 2,3,4 में आयोजित किया जा रहा है। पुस्तक मेले की शुरुआत 25 फरवरी यानी शनिवार को होगी, जोकि 5 मार्च तक चलेगा। फ्रांस गेस्ट ऑफ ओनर रहेगा। खास बात है कि इस बार पुस्तक मेले में करीब 2000 स्टाल रहेंगी। वहीं एक हजार के आसपास प्रकाशकों के रहने की संभावना है।

दो साल बाद फिजिकल मोड में रहा पुस्तक मेला

बता दें कि दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाले पुस्तक मेले की थीम आजादी का अमृत महोत्सव होगी। एनबीटी के निदेशक युवराज मालिक ने प्रेस वार्ता में कहा कि दो साल बाद फिजिकल मोड में पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला इस बार दोगुने आकार में किया जा रहा है। थीम पेवेलियन के अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति और जी 20 पर भी विशेष पेवेलियन होगा।

शिक्षा मंत्री पुस्तक मेले का करेंगे उद्घाटन

युवराज मलिक ने आगे कहा कि चिल्ड्रन पेवेलियन भी रहेगा। एम्फी थियेटर में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। एनबीटी के 50 साल पूरे होने पर एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। सभी भाषाओं की पुस्तकें होंगी। मेले का उद्घाटन दोपहर ढाई बजे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे।

फ्रेंच एम्बेसी के काउंसिलर एमैन्यूल लेबरुन ने कहा कि मेले में फ्रांस की करीब दो हजार पुस्तकें प्रदर्शित होंगी। वहां के 16 लेखकों का एक प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है। फ्रांस के करीब 60 कलाकर भी मेले में अपने देश की संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे।

यमुना को साफ करने के लिए नरेला में बनेगा एसटीपी, मनीष सिसोदिया ने परियोजना को दी मंजूरी

एनटीवी संवाददाता

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यमुना को स्वच्छ करने के लिए नरेला में एसटीपी व दो सीवर पंपिंग स्टेशन के निर्माण को बनाने की मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से 4.17 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही झील का कायाकल्प होगा।

नई दिल्ली। यमुना को वर्ष 2025 तक साफ करने और दिल्ली वासियों को 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनधिकृत कालोनियों को सीवर लाइन से जोड़ने के साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नरेला विधानसभा क्षेत्र के जिंदपुर में 22 एमजीडी क्षमता वाले सीवर पंपिंग स्टेशन (एसपीएस) व 15 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) क्षमता वाले एसटीपी और हिरंकी में नौ एमजीडी एसपीएस के निर्माण की परियोजना को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से नरेला और बुराड़ी की 40 अनाधिकृत आलोनियों और 14 गांवों के लगभग 4.17 लाख लोगों को लाभ होगा।

यमुना में गिरेगा शोधित पानी

जिंदपुर में एसटीपी बनने से 12.45 एमजीडी सीवर का पानी यमुना में शोधित होकर गिरेगा। शोधित पानी बागवानी में उपयोग करने के साथ ही झीलों का कायाकल्प किया जाएगा। सीवर के पानी की बायोकेमिकल आक्सीजन डिमांड (बीओडी) 250 तक होती है। गंदे पानी को शोधित कर 10 तक लाया जाता है। सीवर के शोधित पानी में बीओडी और दूसरा सीओडी (रासायनिक आक्सीजन डिमांड) को देखा जाता है। बीओडी पानी में आक्सीजन की मात्रा है।

दिल्ली में जल्द ही एग्रीगेटर नीति लागू होने जा रही है।

वहीं, सीओडी पानी में कुल कार्बनिक पदार्थों के रासायनिक आक्सीकरण के लिए आवश्यक आक्सीजन की मात्रा है। इसके अलावा टोटल सस्पेंडेड सालिड टीएसएस (टीएसएस) भी पानी की गुणवत्ता जांचने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। वर्तमान डीपीसीसी मानदंडों के अनुसार बीओडी 10 मिलीग्राम प्रति ग्राम से कम और टीएसएस 10 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होना चाहिए। जिंदपुर में आधुनिक तकनीक से लैस एसटीपी के निर्माण से इसमें मदद मिलेगी।

दो एसपीएस से सीवर का पानी पहुंचेगा एसटीपी

सीवर के पानी को पंप कर एसटीपी तक पहुंचाने के लिए जिंदपुर में 22 एमजीडी और हिरंकी में नौ एमजीडी क्षमता वाले एसपीएस बनाने का फैसला लिया है। सीपीएस स्टेशनों की निगरानी आइओटी (इंटरनल आफ थींग्स) निगरानी उपकरण के जरिये की जाएगी। इस इलेक्ट्रानिक उपकरण में लगे सेंसर से पपिंग स्टेशन में सीवर का गंदा पानी एक तय स्तर तक भरने या किसी तरह की खराबी होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अलर्ट चला जाएगा।

इन अनधिकृत कालोनियों और गांवों को होगा फायदा

इब्राहिमपुर, मुखमेलपुर, कादीपुर, नंगलीपूना, कुशक-1, कुशक-2, गढ़ी खसरू, जिंदपुर, अलीपुर, खेड़ा कलां, बुधपुर, हिरंकी, मोहम्मदपुर, रमजानपुर, कुशक-3, नरेला की शिव एनक्लेव, जिंदपुर एक्सटेंशन, जीतराम कालोनी, लक्ष्मण कालोनी, खेराकलां, स्वरूपनगर, सुल्लतानपुर डबास, बालाजी एनक्लेव, दुर्गा एनक्लेव, इब्राहिमपुर एक्सटेंशन, शास्त्रीपार्क, कुशक एक्सटेंशन, प्रदीप विहार, कादीपुर एक्सटेंशन, दुर्गा एनक्लेव।

MCD स्थायी समिति का चुनाव फिर से कराने पर अड़ी BJP, मनोज तिवारी बोले- AAP ने हमारे पार्षदों पर किया हमला

दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि गुप्त मतदान की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए मोबाइल व कलम नहीं ले जाने के लिए आप के नेता सदन मुकेश गोयल के प्रस्ताव को भाजपा ने स्वीकार किया।

नई दिल्ली। भाजपा ने आम आदमी पार्टी (आप) पर स्थायी समिति के चुनाव में एक सोची समझी साजिश के तहत हंगामा करने और भाजपा पार्षदों पर हमला करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि जब महापौर व उपमहापौर के चुनाव में मोबाइल व कलम ले जाने पर प्रतिबंध था तो स्थायी समिति के चुनाव में इसे ले जाने की अनुमति क्यों दी गई? यह निष्पक्ष गुप्त मतदान की प्रक्रिया का उल्लंघन है। उन्होंने 10 मत पत्र आप पार्षदों के कब्जे में होने का आरोप लगाया। कहा कि स्थायी समिति का चुनाव फिर से होना चाहिए।

AAP पार्षदों ने भाजपा पार्षदों पर किया हमला

प्रेस वार्ता में प्रदेश भाजपा के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने वीडियो क्लीप दिखाकर आप पार्षद देवेंद्र कुमार पर यमुना विहार के पार्षद प्रबोध गुप्ता को थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में आप पार्षदों ने इसी तरह से भाजपा पार्षदों पर हमला व हंगामा किया।

दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि गुप्त मतदान की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए मोबाइल व कलम नहीं ले जाने के लिए आप के नेता सदन मुकेश गोयल के प्रस्ताव को भाजपा ने स्वीकार किया। महापौर व उपमहापौर का चुनाव शांतिपूर्ण हुआ। बाद में महापौर ने स्थायी समिति के चुनाव में मोबाइल व कलम ले जाने की अनुमति दे दी जिसका भाजपा पार्षदों ने विरोध किया तो आप पार्षदों ने हमला कर दिया।

मोबाइल ले जाने को लेकर हुआ विवाद

सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि महापौर की तुलना में उपमहपौर चुनाव में आप को कम वोट मिले। इससे आप को लगा कि उसके पार्षद स्थायी समिति के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट देंगे। इस कारण महापौर ने स्थायी समिति के चुनाव में मोबाइल व कलम ले जाने की अनुमति दे दी। आप पार्षदों ने मोबाइल से मतदान की फोटो मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व संजय सिंह को भेजी है। यह गुप्त मतदान के अधिकार का उल्लंघन है।

निगम के सचिव भगवान दास ने बुधवार रात 9.50 पर पत्र लिखकर दस मत पत्र मतदान पेटी में नहीं होने और चुनाव प्रक्रिया को सही तरह से होने की बात कही है। सांसद ने कहा कि मतदान पेटी को सील किए बिना महापौर के कमरे में रखा गया। भाजपा पार्षदों की अनुपस्थिति में बिना वीडियो रिकार्डिंग के इसे तड़के तीन बजे महापौर ने उसे सील किया है। सदन की बैठक नौ बार स्थगित की गई। महापौर प्रत्येक बार देरी से सदन में पहुंची। इस बीच वह आप नेताओं से निर्देश लेती रहीं।

आधी रात कार सवार ने मचाया उत्पात, महिला को कुचलने का प्रयास, विरोध पर सुरक्षाकर्मी का पकड़ा कॉलर

बीटा दो कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर चाई तीन स्थित यूनिटेक हाईटेक सोसाइटी में मंगलवार आधी रात 12 बजे कार सवार व्यक्ति ने जमकर उत्पात मचाया। व्यक्ति ने तेज रफ्तार करीब 80 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से कार सोसाइटी के अंदर दौड़ाई।

ग्रेटर नोएडा। बीटा दो कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर चाई तीन स्थित यूनिटेक हाईटेक सोसाइटी में मंगलवार आधी रात 12 बजे कार सवार व्यक्ति ने जमकर उत्पात मचाया। आरोप है कि व्यक्ति ने तेज रफ्तार करीब 80 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से कार सोसाइटी के अंदर दौड़ाई।

बाल-बाल बची महिला

महिला को कुचलने का प्रयास किया। हालांकि महिला बाल-बाल बच गई। कार पोल से जा टकराई। टक्कर से बिजली का पोल टूट कर जमीन पर गिर गया। तेज रफ्तार में कार चलाने का सुरक्षाकर्मी ने विरोध किया तो आरोपित ने उसका कालर पकड़ लिया। सुरक्षाकर्मी को गालियां दी गई।

पुलिस पर रिपोर्ट न दर्ज करने का आरोप

पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की। आरोप है कि पुलिस ने मामले में रिपोर्ट नहीं दर्ज की है। पीड़ित राजकुमार ने बताया कि वह चीफ सुरक्षा अधिकारी है। मंगलवार रात उनकी ड्यूटी सोसाइटी में थी। रात 12 बजे के करीब सोसाइटी में रहने वाला व्यक्ति तेज रफ्तार में कार लेकर अंदर घुसा।

पुलिस बोलीं- मामला संज्ञान में नहीं

कई रांउड कार सोसाइटी में घुमाने के बाद वह पोल से टकरा गया। सुरक्षागार्ड ने विरोध किया तो आरोपित ने उसके साथ गलत व्यवहार किया। पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद से वह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोतवाली के चक्कर काट रहा है, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं है।

शराब के नशे में धुत्त था आरोपित

पीड़ित ने बताया कि घटना के दौरान आरोपित शराब के नशे में धुत था। आरोपित ने सुरक्षागार्ड को धमकी दी कि वह अपना काम करे। घटना के बाद का वीडियो सुरक्षाकर्मी ने बनाया है, जिसमें सोसाइटी का पोल टूटा हुआ जमीन पर गिरा दिख रहा है।

20 खातों में मिला 50-50 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन, यूफ्लेक्स कंपनी पर IT की रेड में खुलासा

अब तक जब्त दस्तावेजों के आधार पर जांच टीम करीब 500 करोड़ रुपये के टैक्स चोरी का अनुमान लगा रही है। हालांकि अभी जांच को दो दिन ही हुए हैं जिसमें जांच का दायरा बढ़ा है बुधवार को सर्च में पांच स्थान और शामिल हो गए हैं।

नोएडा। आयकर चोरी के लिए यूफ्लेक्स कंपनी की ओर से 20 ऐसे बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया जो बहुत ही निम्न आय वर्ग के लोगों के हैं। वह एक-एक कमरे के मकान में रहते हैं। उनके खातों में 50-50 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन किया गया है। यह बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य आयकर की जांच टीम के हाथ लगा है। जांच टीम ने अब तक कार्रवाई में 150 करोड़ रुपये के बोगस ट्रांजेक्शन की पुष्टि कर ली है। एक पक्ष ने बोगस ट्रांजेक्शन की बात को स्वीकार कर लिया है जबकि दूसरा पक्ष इन्कार कर रहा है। कंपनी की जम्मू फैक्ट्री से 100 करोड़, नोएडा सेक्टर-4 व 57 से 150 करोड़ रुपये से अधिक के बोगस लेन-देन के कागजात बरामद हुए हैं। 15 लाकर सामने आ चुके हैं।

अब तक जब्त दस्तावेजों के आधार पर जांच टीम करीब 500 करोड़ रुपये के टैक्स चोरी का अनुमान लगा रही है। हालांकि अभी जांच को दो दिन ही हुए हैं, जिसमें जांच का दायरा बढ़ा है, बुधवार को सर्च में पांच स्थान और शामिल हो गए हैं। नोएडा में 32 स्थानों समेत देशभर में 83 जगहों पर आयकर की सर्च जारी है। एनसीआर में 600 टीम के साथ देश के विभिन्न स्थानों पर 150 टीम अतिरिक्त रूप से जांच कर रही है। जांच टीम ने अब तक 10 शेल कंपनियां पकड़ी हैं जिनके जरिये बोगस ट्रांजेक्शन किया गया। जांच की जा रही है कि इनमें कहां से रकम आई और कहां भेजी गई है। यूफ्लेक्स की 10 विदेशी कंपनियां भी रडार पर हैं जिसमें भारी ट्रांजेक्शन हुआ है।

गंगाजल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में तकनीकी खामी, 2 दिन नोएडा को भी नहीं मिलेगा पानी

सिद्धार्थ विहार प्लांट के एक पाइप में लीकेज आ गई है। इस लीकेज बड़े स्तर पर आई है। इसमें पाइप को बदलना भी पड़ सकता है। बुधवार दोपहर तक इंजीनियर इसे ठीक करने में जुटे रहे लेकिन लेकिन वह ठीक नहीं हो सका।

गाजियाबाद। सिद्धार्थ विहार के गंगाजल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में तकनीकी खामी आने के बाद उसे बंद कर दिया गया है। इसे ठीक करने में दो दिन का समय लग सकता है। ऐसे में नोएडा, इंदिरापुरम और सिद्धार्थ विहार को बृहस्पतिवार और शुक्रवार को गंगाजल नहीं मिलेगा। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा अपने क्षेत्र में नलकूप से प्रभावित इलाकों में पानी की आपूर्ति की जाएगी। सिद्धार्थ विहार में 245 एमएलडी की क्षमता का प्लांट है। इस प्लांट से 80 प्रतिशत पानी नोएडा, 15 प्रतिशत जीडीए और पांच प्रतिशत आवास विकास के क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की जाती है। सिद्धार्थ विहार प्लांट के एक पाइप में लीकेज आ गई है। इस लीकेज बड़े स्तर पर आई है। इसमें पाइप को बदलना भी पड़ सकता है। बुधवार दोपहर तक इंजीनियर इसे ठीक करने में जुटे रहे लेकिन लेकिन वह ठीक नहीं हो सका।

ऐसे में प्लांट को सूखाकर इसका लीकेज ठीक करवाया जाएगा। पहले पूरे प्लांट को खाली कराया जाएगा। इसके बाद उसे ठीक किया जाएगा। गंगाजल प्लांट के अधिशासी अभियंता उन्मेश शुक्ला ने बताया कि दो दिन तक गंगाजल की आपूर्ति सिद्धार्थ विहार से नहीं होगी। इस संबंध में नोएडा प्राधिकरण को सूचना दे दी गई है। वहीं, 120 एमएलडी वाले प्रताप विहार प्लांट से पूर्व की भांति गंगाजल की आपूर्ति होती रहेगी। वैशाली और वसुंधरा क्षेत्र को पानी मिलता रहेगा।

पानी माफिया होंगे सक्रिय

जब भी गंगाजल का प्लांट बंद होता उसी दौरान पानी माफिया सक्रिय हो जाते हैं। माफिया पानी के जार लेकर इंदिरापुरम क्षेत्र में सक्रिय जाएंगे। दो गुना कीमत पर पानी बेचना शुरू कर देंगे। इंदिरापुरम के शक्ति खंड दो के मनोज कुमार का कहना है कि गंगा जल बंद करने के बद नलकूप से पर्याप्त पानी की आपूर्ति की जानी चाहिए। जिससे लोगों को पानी की परेशानी न हो।

साइबर ठग ने वर्दी पहनकर किया वीडियो कॉल, कहा- आप आतंकी गतिविधियों में हैं लिप्त, दीजिए 1 लाख

एनटीवी न्यूज

साइबर ठग लोगों को नई-नई तरह से ठगने के तरीके निकॉल रहे हैं। कविनगर के शास्त्रीनगर में रहने वाले एक कारोबारी को आतंकी गतिविधियों में लिप्त बताकर साइबर ठगों ने उनसे रकम ऐंठने का प्रयास किया।

गाजियाबाद। साइबर ठग लोगों को नई-नई तरह से ठगने के तरीके निकाल रहे हैं। कविनगर के शास्त्रीनगर में रहने वाले एक कारोबारी को आतंकी गतिविधियों में लिप्त बताकर साइबर ठगों ने उनसे रकम ऐंठने का प्रयास किया। आरोपित लगातार उन्हें कॉल कर ब्लैकमेल कर रहे हैं। मामले में उन्होंने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस साइबर सेल की मदद से मामले की जांच कर रही है।

शास्त्रीनगर डी-ब्लाक के रहने वाले विपिन ओझा फेब्रिकेशन कारोबारी हैं। उनका कहना है मंगलवार को उनके पास अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने अपने को सुरक्षा एजेंसी से बताते हुए कहा कि उनके नाम मुंबई से एक पार्सल आया है। पार्सल में चार एटीएम कार्ड, चार सिम कार्ड व तीन पासपोर्ट हैं। आरोपित ने कहा कि जांच करने पर पता चला है कि यह पार्सल टेरर फंडिग से जुड़ा है। आरोपित ने उन्हें आतंकी गतिविधियों से जुड़ा बताते हुए डराने का प्रयास किया। कारोबारी ने इस तरह के पार्सल से इन्कार कर दिया। इसके तुरंत बाद आरोपित ने उन्हें वीडियो कॉल की और दूसरी तरफ से वर्दी पहने एक व्यक्ति से बात कराई। वर्दी पहने व्यक्ति ने भी उन्हें आतंकी गतिविधियों से जुड़ा होना बताया और तत्कॉल मुंबई आने के लिए कहा। आरोपितों ने धमकी दी कि वह मुंबई नहीं आए तो टीम घर से उठाकर ले जाएगी। आरोपितों ने वेरीफेशन का झांसा दे उनका आधार व अन्य दस्तावेज ले लिए।

कारोबारी का कहना है कि बाद में उनके पास दूसरे नंबर से कॉल आई और दूसरी तरफ से बोल रहे व्यक्ति ने अपने को हेडक्वार्टर का अधिकारी बताते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी। मामला निपटाने के लिए उसने एक लाख रुपये की मांग की। इस पर उन्हें शक हुआ और उन्होंने तत्कॉल पुलिस से शिकायत की। एसीपी कविनगर अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की साइबर सेल की मदद से जांच की जा रही है।

बोरे में बंद करके फेंके गए कुत्ते, 2 अधिकारियों पर हुई कार्रवाई

पहले चरण में नगरायुक्त डा. नितिन गौड़ ने कार्य में लापरवाही बरतने और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डा.अनुज कुमार सिंह से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित रिवर हाइट्स सोसायटी में स्ट्रीट डाग्स के लिए बनाए गए फीडिंग प्वाइंट्स का मामला अब गरमा गया है। सोसायटी द्वारा फीडिंग प्वाइंट्स में रखे गए कुत्तों को मुक्त कराने के लिए पीएफए ट्रस्ट की संस्थापक आशिमा शर्मा ने नगरायुक्त से मांग की तो सोसायटी के लोगों ने कुत्तों को बोरे में बंद करके फेंक दिया।

वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई

इसका वीडियो सोशल मीडिया प्रसारित होने और इसकी नगरायुक्त को लिखित शिकायत करने पर संबंधित अधिकारियों एवं सोसायटी के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पहले चरण में नगरायुक्त डा. नितिन गौड़ ने कार्य में लापरवाही बरतने और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डा.अनुज कुमार सिंह से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

जारी आदेश में लिखा है कि इस प्रकरण में मौके पर जाकर फीडिंग प्वाइंट्स से कुत्तों को सुरक्षित तरीके से मुक्त कराने के निर्देश दिये गए थे लेकिन अधिकारियों ने इन आदेशों का

अनुपालन नहीं किया है। यह अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। नोटिस भेजकर नगरायुक्त ने दो दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। इसके अलावा पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डा.आशीष त्रिपाठी के वेतन पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है।

पुलिस को दी गई शिकायत

नगरायुक्त के सख्त रूख को भांपकर अधीनस्थ अधिकारियों ने कुत्तों को बोरे में बंद करके फेंके जाने को लेकर सोसायटी की एओए के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआइआर दर्ज कराने को नंदग्राम थाने में तहरीर भी दे दी है। बता दें कि इस प्रकरण को लेकर बुधवार को सोसायटी के लोगों ने नगर निगम कार्यालय पर धरना भी दिया था। पीएफए ट्रस्ट की संस्थापक आशिमा शर्मा का कहना है कि नियमानुसार कुत्तों को बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता है। उधर सोसायटी की एओए के अध्यक्ष सुबोध त्यागी का कहना है कि सोसायटी ने खुद की छह एकड़ पर जमीन पर स्ट्रीट डाग्स को खाना खिलाने के लिए फीडिंग प्वाइंट्स बनाया है। उनका आरोप है कि पीएफए ट्रस्ट के लोग बिना वजह छह फीडिंग प्वाइंट्स को बंद कराने का प्रयास कर रहे हैं।

रिश्वतकांड में दो रेलवे अधिकारी समेत 5 गिरफ्तार, CBI दिल्ली की टीम ने आगरा और मथुरा से किया अरेस्ट

घूस लेकर ठेकेदार को लाभ पहुंचाने व रेलवे को नुकसान पहुंचाने के आरोप में दो रेलवे अधिकारियों समेत ठेकेदार फर्म के सुपरवाइजर निदेशक व प्रबंधक निदेशक को गिरफ्तार कर सीबीआइ दिल्ली की टीम ने गाजियाबाद स्थित सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश परवेंद्र कुमार शर्मा की अदालत में पेश किया।

गाजियाबाद। घूस लेकर ठेकेदार को लाभ पहुंचाने व रेलवे को नुकसान पहुंचाने के आरोप में दो रेलवे अधिकारियों समेत ठेकेदार फर्म के सुपरवाइजर, निदेशक व प्रबंधक निदेशक को गिरफ्तार कर सीबीआइ दिल्ली की टीम ने गाजियाबाद स्थित सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश परवेंद्र कुमार शर्मा की अदालत में पेश किया। मंगलवार को पेश किए गए चार आरोपितों के पांच दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड को अदालत ने मंजूरी दी, जबकि बुधवार को पेश किए गए आरोपित को जेल भेजने के आदेश दिए। उसके कस्टडी रिमांड की अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी।

पद का दुरुपयोग का आरोप

सीबीआइ के लोक अभियोजक ईश्वर ने बताया कि रेलवे के आगरा मंडल के डीआरएम कार्यालय में मुकेश कुमार डिप्टी चीफ सिग्नल एंड टेलीकाम इंजीननियर कंस्ट्रक्शन के पद पर कार्यरत हैं, जबकि विजय सिंह मथुरा में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर तैनात हैं। दोनों पर आरोप है कि इन्होंने पद का दुरुपयोग कर ठेकेदार फर्म शिवकृति इंटरनेशनल लिमिटेड को अनैतिक लाभ पहुंचाया। सीबीआइ को पुख्ता सूचना मिली थी कि फर्म के फर्जी बिल व कम काम के एवज में ज्यादा भुगतान के बिल पास करने के लिए विजय सिंह ने उक्त फर्म के सुपरवाइजर ब्रह्मानंद से पांच लाख रुपये रिश्वत मांगी थी।

पांच लाख रुपये की ली रिश्वत

ब्रह्मानंद ने फर्म के निदेशक आदित्य व प्रबंध निदेशक शिव दयाल शर्मा से पांच लाख रुपये लिए और सोमवार को मथुरा में विजय सिंह को देने पहुंचा। तभी सीबीआइ इंस्पेक्टर वीर ज्योति के नेतृत्व में टीम ने रिश्वत लेते व देते हुए दोनों को दबोचा। इनसे मिली जानकारी के बाद सीबीआइ ने ठेकेदार फर्म के निदेशक व प्रबंधक निदेशक को दबोचा और मंगलवार को गाजियाबाद स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत में पेश किया। सीबीआइ की अर्जी पर मंगलवार को अदालत ने चारों के कस्टडी रिमांड मंजूर दी। ठेकेदार फर्म के सुपरवाइजर, निदेशक व प्रबंधक निदेशक से पूछताछ के बाद सीबीआइ को मुकेश कुमार को गत 23 जनवरी को दो लाख व 17 फरवरी को 1.23 लाख रुपये रिश्वत देने की जानकारी मिली। इसके बाद सीबीआइ ने इसे आगरा से गिरफ्तार कर बुधवार को विशेष अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे 14 दिन के लिए जेल भेजने के आदेश दिए।

इनसाइड

दादरी विधायक के आवास का घेराव करने जा रहे किसान नेता सुखबीर खलीफा नजरबंद

दादरी विधायक तेजपाल नागर के आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। नजरबंद करने से नाराज सुखबीर खलीफा के समर्थक घर के बाहर स्थित पार्क में धरने पर बैठ गए।

नोएडा। भारतीय किसान परिषद के सदस्यों ने दादरी विधायक तेजपाल नागर के आवास के घेराव की घोषणा के बाद पुलिस ने किसान नेता सुखबीर खलीफा को उनके सेक्टर 70 स्थित आवास पर नजरबंद कर दिया। सुखबीर खलीफा के आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। नजरबंद करने से नाराज सुखबीर खलीफा के समर्थक घर के बाहर स्थित पार्क में धरने पर बैठ गए।

परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा का कहना है कि क्षेत्र की जनता विभिन्न समस्याओं से त्रस्त है और अपनी मांगों को उन्होंने कई बार विधायक के समक्ष उठाया था। इसके बावजूद जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया। विधायक जनता की अनदेखी कर रहे हैं। जनता की आवाज को विधायक तक पहुंचाने के लिए ही परिषद ने उनके आवास के घेराव की घोषणा की थी।

सुखबीर खलीफा के आवास के बाहर पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण

पुलिस के बल पर सत्ताधारी विधायक आम जनता की आवाज को दबा नहीं सकते हैं। लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है। नजरबंद किए जाने से उनके हौसले पस्त होने वाले नहीं हैं। विरोध का यह सिलसिला थमेगा नहीं। जब तक आम जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तब तक विरोध का यह सिलसिला जारी रहेगा। वहीं सुखबीर खलीफा के आवास के बाहर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे। किसानों ने यहां हुंकार भरी।

गौरतलब है ग्रेटर नोएडा में दादरी के पास नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन का विद्युत उत्पादन केंद्र है। यह संयंत्र लगाने के लिए सरकार ने करीब 35 वर्ष पूर्व इलाके के 24 गांवों में भूमि अधिग्रहण किया था। किसानों का कहना है कि उस वक्त भूमि अधिग्रहण की एवज में मिलने वाला मुआवजा समान नहीं था। मतलब, किसी गांव में कम और किसी गांव में ज्यादा मुआवजा भुगतान किया गया। तभी से किसान समान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा एनटीपीसी में नौकरियां और इन गांवों के विकास की मांग भी किसान करते रहे हैं। अब इन्हीं मांगों को पूरा करवाने के लिए किसान एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट के बाहर प्रदर्शन कर रहे है।

खरीदने की सोच रहे हैं KIA की नई Carens तो पहले जान लें इसका वेटिंग पीरियड

Kia Carens को वर्तमान में प्रीमियम प्रेस्टीज प्रेस्टीज प्लस लग्जरी और लग्जरी प्लस वेरिएंट में सेल किया जाता है। अगर आप इस कार को खरीदने की प्लैनिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस कार के वेटिंग पीरियड के बारें में पता होना चाहिए।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में किआ ने अपनी पहचान काफी जल्दी बना ली है, लोगों को इसकी कार काफी पसंद भी आ रही है। किआ की करैन्स ने एक महीने में भी सबसे अधिक ब्रिकी प्राप्त की है। अगर आप भी किआ करैन्स को खरीदने की प्लैनिंग कर रहे हैं तो इससे पहले इस कार की वेटिंग पीरियड के बारें में जान ले, इसकी बढ़ती डिमांड के कारण, वेटिंग पीरियड भी अधिक होती जा रही है।

वेटिंग पीरियड

Kia Carens को बाजार में आए एक साल हो चुके हैं और ये देश में सबसे अधिक बिकने वाली एमपीवी में से एक है। इसे कंपनी ने छह और सात सीटर में पेश किया है। इस कार का वेटिंग पीरियड 3 महीने से अधिक का है। वहीं 1.5L पेट्रोल इंजन मैन्युअल ट्रांसमिशन के साथ प्रीमियम और प्रेस्टीज वेरिएंट के लिए केवल 7 से 8 सप्ताह की वेटिंग पीरियड है।

Kia Carens वेटिंग पीरियड

Kia Carens को वर्तमान में प्रीमियम, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज प्लस, लग्जरी और लग्जरी प्लस वेरिएंट में सेल किया जाता है। 1.5 लीटर डीजल इंजन इन सभी ट्रिम वेरिएंट्स में आती है जिसकी वेटिंग पीरियड 11 से 12 सप्ताह (3 महीने से कम) है। 1.5L चार-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन 115 PS का अधिकतम पावर आउटपुट और 144 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।

फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो इस कार में छह एयरबैग, ABS, ESC, HAC, VSM, DBC, TPMS, रिवर्सिंग सेंसर, BAS, आदि जैसे सेफ्टी फीचर्स भी शामिल हैं। कुछ अन्य विशेषता हाइलाइट्स में Apple CarPlay और Android Auto के साथ 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। कनेक्टिविटी, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, मिडिल रो के लिए वन-टच टंबल फंक्शन, ऑल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एंबियंट लाइटिंग।

इंजन

किआ Carens को तीन इंजन ऑप्शन में आती है। 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल- इसमें 115 पीएस की पावर और 143 एनएम का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। यह एक मैनुअल और एक सीवीटी या आईवीटी गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आता है। 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन- 115 पीएस की पावर और 250 एनएम की पीक टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। सेल्टॉस की तरह, इसे भी 6-स्पीड ऑटोमैटिक और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है। 1.4 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन सबसे पावरफुल 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 140 पीएस और 242 एनएम का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इसे मैन्युअल और 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ पेश किया गया है।

इनसाइड

MPV से लेकर SUV तक दमदार कारों को लेकर आएगी Toyota, जानिए इनमें क्या होगा खास

हाल के दिनों में 2023 Toyota Innova Crysta diesel की बुकिंग वाहन निर्माता कंपनी ने शुरू की थी। ये कार कुल चार वेरिएंट्स में आती है। कंपनी इस साल कई कारों को लॉन्च करने वाली है।

नई दिल्ली। जापान की वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा इस साल अपनी कई दमदार कारों को लॉन्च करने वाली है। इसमें एमपीवी है और नई एसयूवी भी है। हाल के दिनों में Toyota ने Innova Hycross को पेश किया था और यह खरीदारों के बीच काफी हिट है। लोग इस कार को काफी अधिक पसंद कर रहे हैं। आज हम आपके लिए टोयोटा की आने वाली गाड़ियों की लिस्ट लेकर आए हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि टोयोटा एक एमपीवी लेकर आने वाली है। एमपीवी का मतलब होता है- मल्टी पर्पज व्हीकल। आप इसके नाम से ही पहचान गए होंगे कि इसके इस्तेमाल आप कई कामों के लिए कर सकते हैं। एमपीवी सेगमेंट भारतीय बाजार में काफी लोकप्रिय है। इनको डिजाइन ही कुछ इस तरीके से किया जाता है कि इसमें आप कई समान लेकर जा सकें। एमपीवी सात और पांच सीटर में आती है।

2023 Toyota Innova Crysta diesel

हाल के दिनों में ही वाहन निर्माता कंपनी ने इस कार की बुकिंग शुरु की थी। ये कार कुल चार वेरिएंट्स में आती है- जी, जीएक्स, वीएक्स और जेडएक्स। इसके साथ ही इसमें पांच कलर ऑप्शन- व्हाइट पर्ल क्रिस्टल शाइन, सुपर व्हाइट, सिल्वर, एटिट्यूड ब्लैक और अवंत-गार्डे ब्रॉन्ज मिलते हैं। वाहन में फीचर्स की बात करें तो ड्राइवर के लिए 8 तरह से एडजस्ट होने वाली इलेक्ट्रिक सीटें, 8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी और एंबिएंट लाइटिंग मिलती है। सेफ्टी के लिहाज से इसमें सात एयरबैग, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, वाहन स्थिरता नियंत्रण और हिल स्टार्ट असिस्ट भी मिलता है।

Toyota A15 SUV Coupe

टोयटा इस साल के अंत तक देश में अपनी एक नई एसयूवी कूप कोडनेम A15 को लॉन्च करेगी। नई एसयूवी कूप बंद हो चुके अर्बन क्रूजर के रिप्लेसमेंट के तौर पर बाजार में आएगी। इसका मुकाबला - Hyundai Venue, Kia Sonet, Renault Kiger और Nissan Magnite से होगा। नई कूप मारुति की YTB SUV कूप पर बेस्ड होगी, जिसे कंपनी ने ऑटो एक्सपो 2023 में पेश किया था।

मारुति और हुंडई की इन कारों के लिए सेट हो चुका है स्टेज, बुकिंग भी ओपन

NEXT-GEN HYUNDAI VERNA की वाहन निर्माता कंपनी ने बुकिंग भी चालू कर दी थी। मारुति से लेकर हुंडई इस साल अपनी कारों को लॉन्च करने के लिए पुरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही बुकिंग भी चालू कर दी है।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में मारुति ने 2022 में नए Brezza, Baleno, Alto K10 और Grand Vitara जैसी कई शानदार मॉडल को लॉन्च किया था। लेकिन कंपनी इस साल भी बाजार में कई नए वाहनों को लेकर आने वाली है। अगले 3 से 4 महीनों में कंपनी 2 नए मॉडल को पेश करेगी जिससे एसयूवी के पोर्टफोलियो में विस्तार होगा। दूसरी ओर हुंडई भी अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करेगी, वहीं मिड साइज सेडान - न्यू-जेन वेरना सेडान भी लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

MARUTI SUZUKI FRONX

2023 ऑटो एक्सपो में वाहन निर्माता कंपनी ने इस कार को शोकेस किया था। ये नया मॉडल नेक्सा प्रीमियम डीलरशिप नेटवर्क के जरिए बेचा जाएगा। आपको बता दें, नए मॉडल का डीलर डिस्पैच शुरु हो चुका है। अगर आप इस कार को खरीदना चाहते हैं तो 11 हजार रुपये की टोकन राशि देकर नए क्रॉसओवर को ऑनलाइन या अधिकृत डीलरशिप पर जाकर इस कार को बुक करा सकते हैं। नया मॉडल मार्च - अप्रैल 2023 में लॉन्च हो सकता है। ये 5 ट्रिम्स- सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा+, ज़ेटा और अल्फा में आएगी। इस कार में आपको दो इंजन ऑप्शन एक 1.0-लीटर बूस्टरजेट पेट्रोल और एक 1.2-लीटर डुअल-जेट पेट्रोल मिलेगा। टर्बो इंजन को 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेश किया जा सकता है। जबकि NA यूनिट 5-स्पीड मैनुअल या AMT के साथ आती है।

MARUTI SUZUKI JIMNY SUV

2023 ऑटो एक्सपो में मारुति ने इस कार का अनावरण किया था, मारुति सुजुकी जिम्नी 5-डोर 2023 तक बाजार में ब्रिकी के लिए आ जाएगी। इस कार को आप 15 हजार रुपये टोकन राशि देकर बुक करा सकते हैं। इसे आप ऑनलाइन या फिर अधिकृत डीलरशिप पर जाकर बुक करा सकते हैं। इसे नेक्सा प्रीमियम डीलरशिप नेटवर्क के जरिए बेचा जाएगा। नया मॉडल दो ट्रिम -जीटा और अल्फा और कुल 4 वेरिएंट में आएगा। इसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपये से 14 लाख रुपये के बीच हो सकती है। इसे 1.5-लीटर K15B 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित किया जाता है। एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 103bhp की पावर और 134.2Nm का टार्क जनरेट करने में सक्षम है। ट्रांसमिशन ऑप्शन में 5-स्पीड मैनुअल और 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक मिलता हैं।

NEXT-GEN HYUNDAI VERNA

Hyundai ने आधिकारिक तौर पर अपनी आने वाली नेक्स्ट-जनरेशन की वेरना सेडान का टीज़र इमेज जारी किया था। इसके साथ ही इस कार की बुकिंग भी चालू कर दी थी, इस कार को आप मात्र 25 हजार रुपये में ऑनलाइन या ऑफलाइन डिलरशिप पर जाकर बुक करा सकते हैं । कंपनी इसे लॉन्च जल्द ही कर सकती है। इसके अलावा नई Verna अपनी कैटेगरी में सबसे पावरफुल होगी। यह 1.5-लीटर 4-सिलेंडर एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो जीडीआई पेट्रोल के साथ आएगी।

TESLA लगाएगी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सुपरचार्जर, ऐप या वेबसाइट की मदद से ढूंढ सकेंगे चार्जिंग प्वाइंट

टेस्ला के साथ-साथ जनरल मोटर्स ईवीजीओ पायलट हट्र्ज और अन्य कंपनियां भी अगले दो सालों में हजारों सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क का विस्तार करेगी। टेस्ला ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल करके इन स्टेशनों तक पहुंच सकेंगे।

नई दिल्ली। बाइडेन प्रशासन ने बुधवार को राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर नेटवर्क पर लंबे समय से प्रतीक्षित नियम जारी किए। ईवी की तेज चार्जिंग को सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। लेकिन इसने दिग्गज इलेक्ट्रिक कार कम्पनी टेस्ला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। व्हाइट हाउस टेस्ला सुपरचार्जर्स सहित EV चार्जिंग स्टेशनों के बढ़ते नेटवर्क तक निर्बाध पहुंच प्रदान करना चाहता है। इस नेटवर्क के लिए अमेरिकी सरकार कंपनियों को 7.5 बिलियन डॉलर देने की योजना बना रही है। जो कंपनियां इस फंड में दावा कर रही हैं, उन्हें चार्जिंग कनेक्टर्स के लिए यूएस मानक को अपनाना पड़ेगा। इसे संयुक्त चार्जिंग सिस्टम या CCS के रूप में जाना जाता है और स्मार्टफोन के अनुकूल मानकीकृत भुगतान विकल्पों का उपयोग करना चाहिए। फैसले के तहत अब इलेक्ट्रिक कार की दिग्गज कंपनी टेस्ला कंपनी चार्जिंग स्टेशनों की चेन लगाएगी।

2024 के अंत तक टेस्ला के सुपरचार्जर स्थापित होंगे

2024 के अंत तक टेस्ला के सुपरचार्जर और डेस्टिनेशन चार्जर नेटवर्क से गैर-टेस्ला ईवीएस के लिए कम से कम 7,500 चार्जर उपलब्ध कराए जाएंगे। अमेरिका के सबसे बड़े और विश्वसनीय चार्जिंग नेटवर्क को सभी ड्राइवरों के लिए खोलने की योजना इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी और ये एक गेम -चेंजर भी साबित होगी।

राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि अमेरिकी सड़क अब इलेक्ट्रिक होगी। जल्द ही अपनी कार को चार्ज करना पेट्रोल भरवाने जितना आसान हो जाएगा। जितना समय एक गैस स्टेशन पर लगता है, उतना ही समय ईवी को चार्ज करने में लगेगा।

ईवी चार्जिंग नेटवर्क से मिलेगी ये सुविधा

टेस्ला के चार्जिंग नेटवर्क को खोलने की योजना व्हाइट हाउस की उस योजना का हिस्सा है, ईवी चार्जिंग नेटवर्क सभी अमेरिकियों के लिए सुविधाजनक और विश्वसनीय बनाने में काम कर रहा है, ताकि लोग इसपर अधिक भरोसा करें, इसमें लंबी दूरी की ड्राइविंग भी शामिल है। इसके कारण हर कोई नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस कार को चलाते हैं और किस राज्य में चार्ज करते हैं।

अगले दो सालों में हजारों सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन

टेस्ला के साथ -साथ जनरल मोटर्स, ईवीजीओ, पायलट, हट्र्ज और अन्य कंपनियां भी अगले दो सालों तक हजारों सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क का विस्तार करने के लिए सहमत हो गई हैं, इस पर व्हाइट हाउस का कहना है कि देश के ईवी चार्जिंग लक्ष्यों को पूरा करने के करीब अब हम पहुंच रहे हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि हम कितना ईवी को लेकर सख्त और जागरूक है।

टेस्ला ऐप या वेबसाइट के इस्तेमाल से पहुंच सकेंगे

व्हाइट हाउस ने कहा कि प्रशासन की योजना के तहत, टेस्ला सार्वजनिक स्थानों पर चार्जिंग साइट को लगाएगी। अधिकारियों ने कहा कि सभी ईवी चालक टेस्ला ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल करके इन स्टेशनों तक पहुंच सकेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा कि टेस्ला ने अगले कुछ सालों में सुपर चार्ज के अपने नेटवर्क को तिगुना करने की योजना बनाई है।

कैसे रोकें भ्रष्टाचार?

पीके खुराना

भ्रष्टाचार हमारे जीवन में यूं समा गया है कि उसे अलग से देख पाना संभव ही नहीं लगता। भारतीय शासन व्यवस्था ऐसी बन गई है कि हम भ्रष्टाचार रहित जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाते। जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, रोज़मर्रा के हर काम में भ्रष्टाचार है। लाइन तोडने से लेकर जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार पसरा हुआ है।

परिणाम यह है कि चुनाव जीतना ही सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए उम्मीदवार जीत सुनिश्चित करने के लिए हर तरह के जायज़ और नाजायज़ तरीके अपनाते हैं। स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए शुरुआत हमें जड़ से करनी होगी, यानी चुनाव प्रणाली ऐसी बनानी होगी कि भ्रष्ट तरीकों से चुनाव जीतना संभव न हो सके। भारतीय आदतन भ्रष्ट नहीं हैं, हमारा सिस्टम हमें भ्रष्ट बनने के लिए विवश कर रहा है। उपाय यही है कि हम सिस्टम को मजबूत बनाएं, भ्रष्टाचार की संभावना पर रोक लगाने के उपाय करें ताकि समाज में चल रहे नैतिक पतन पर रोकथाम लग सके और हम विकास के पायदान चढ़ते रह सकें'

भ्रष्टाचार हमारे जीवन में यूं समा गया है कि उसे अलग से देख पाना संभव ही नहीं लगता। भारतीय शासन व्यवस्था ऐसी बन गई है कि हम भ्रष्टाचार रहित जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाते। जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, रोज़मर्रा के हर काम में भ्रष्टाचार है। लाइन तोडने से लेकर जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार पसरा हुआ है। कई बार लगता है मानो भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं रहा। नेता भ्रष्ट हैं, अधिकारी भ्रष्ट हैं, व्यापारी भ्रष्ट हैं, जनता भ्रष्ट है। हमारी रग-रग में भ्रष्टाचार भर गया है। जब सभी भ्रष्ट हैं तो इसे जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लिया गया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी भ्रष्ट सरकारी अधिकारी से लडना 'आ बैल मुझे मार' जैसा है, अतः हम लोग चुपचाप रिश्वत देकर काम करवाना ही ठीक समझते हैं, वरना यह लगभग पक्का है कि उस भ्रष्ट अधिकारी का कुछ बिगड़े या न बिगड़े, पर हमारा काम जरूर अटक जाएगा। भ्रष्टाचार की मकबूलियत इस हद तक की है कि आज से लगभग आधी सदी पहले भी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 'हमारा भारत महान' का नारा दिया था तो समाज में प्रचलित चुटकुलों में '99 प्रतिशत बेईमान, फिर भी मेरा देश महान' शामिल हो गया। हम लोग इन चुटकुलों को पढ़ते थे, हंसते थे और भुला देते थे। हमारा देश गरीब लोगों का अमीर देश है।

यहां प्राकृतिक संसाधनों और खनिज पदार्थों की भरमार है, लेकिन लोग गरीब हैं, गरीबों और अमीरों के बीच की खाई उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। गरीबी से सताया हुआ व्यक्ति इतना विवश हो जाता है कि वह अक्सर अपना अपमान भी चुपचाप सह लेता है। इससे उसका आत्मविश्वास जाता रहता है और समाज में उसका योगदान घटने लगता है। भ्रष्टाचार पर काबू पाने के उपायों के संबंध में लोगों की राय अलग-अलग है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि पहले हमें बदलना होगा, तभी कोई सुधार संभव है। दूसरी ओर प्रशासनिक सुधारों से जुड़े रहे अनुभवी लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार पर काबू पाने का एक ही तरीका है कि सिस्टम में सुधार किया जाए। मेरा अनुभव भी इसी की गवाही देता है। लगभग दो दशक पहले जब मैं छुट्टियां मनाने इंग्लैंड गया था तो हमारे परिवार की महिलाएं खरीददारी के लिए एक बड़े मॉल में गईं। चूंकि उनकी सारी खरीददारी महिलाओं के सामान से संबंधित थी, और बाहर मौसम बहुत सुहावना था, इसलिए मैं कुछ देर के लिए मॉल से बाहर निकल कर पार्किंग में आ गया। मैंने देखा कि पार्किंग में एक जगह चमड़े की नई एक बेल्ट गिरी पड़ी थी। निश्चय ही कोई ग्राहक खरीददारी के बाद अपनी गाड़ी में बैठते समय गलती से बेल्ट वहां गिरा गया था। मैं लगभग 10 मिनट तक देखता रहा।

इस बीच कई गाडियों वाले आए और गए, लेकिन किसी ने भी वह बेल्ट उठाने की कोशिश नहीं की। तभी मॉल का एक कर्मचारी बाहर पार्किंग में आया तो मैंने उसे बताया कि किसी ग्राहक की बेल्ट गिर गई है और वो उसे संभाल ले ताकि यदि ग्राहक वापिस आए तो उसे बेल्ट मिल जाए। मॉल के उस कर्मचारी ने जवाब दिया कि बेल्ट का छूट जाना उनके संज्ञान में है और जो भी व्यक्ति बेल्ट उठाएगा, वे उसका उस दिन की खरीददारी का बिल चेक करेंगे और जांच लेंगे कि क्या उसने उनके मॉल से सचमुच उस दिन बेल्ट खरीदी थी। मॉल के कर्मचारी की उस सूचना ने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। वह बेल्ट वहां दो घंटे से ज्यादा समय से पड़ी थी और पार्किंग में आने वाला हर व्यक्ति उसे देख रहा था तो भी अगर उस बेल्ट को कोई उठा नहीं रहा था तो इसका कारण यह था कि उन्हें पता था कि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से इस बेल्ट पर नजर रखी जा रही है और बेल्ट उठाने वाले व्यक्ति के बिल की जांच की जाएगी। अगर ऐसा भारतवर्ष में हुआ होता तो वह बेल्ट शायद वहां 5 मिनट भी न रह पाती। हमारे देश में महापुरुषों की कमी कभी नहीं रही, हम स्वभाव से आदर्शवादी हैं, फिर भी यदि समाज में नैतिक गिरावट बढ़ती जा रही है तो इसका कारण यही है कि भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए कोई मजबूत सिस्टम उपलब्ध नहीं है। इसका प्रमाण यह है कि विदेशों में बसे भारतीय सफल भी हैं और नैतिक तथा सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार भी। यदि सचमुच भारतीय होने के कारण हम बेईमान होते तो फिर विदेशों में बसे भारतीय भी बेईमान ही होते। विभिन्न अध्ययनों से सिद्ध होता है कि देश का सिस्टम कैसा भी हो, लगभग 10 प्रतिशत लोग ईमानदार होते ही हैं, और कुछ भी कर लें तो भी 10 प्रतिशत के लगभग लोग बेईमानी से बाज़ नहीं आते, जबकि 80 प्रतिशत लोग समाज की स्थितियों के अनुसार ढल जाते हैं। यदि सिस्टम मजबूत हो, बेईमानी पर तुरंत सज़ा होती हो, तो ये लोग बेईमानी की कोशिश नहीं करते, लेकिन यदि वे यह देखें कि बेईमानी करने वाला फल-फूल रहा है, उसे कोई सज़ा नहीं मिल रही, बल्कि वह जीवन का ज्यादा आनंद ले रहा है तो ये 80 प्रतिशत लोग भी बेईमानी पर उतर आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए सिस्टम को मजबूत बनाना आवश्यक है। हमारे समाज की अवनति का कारण ही यह है कि हमारे देश में सत्तारूढ़ लोगों ने अपने निहित स्वार्थों की खातिर सिस्टम को मजबूत बनाने के बजाय या तो सिस्टम बनाया ही नहीं, या फिर जानबूझकर उनमें खामियां छोड़ दीं। हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया ही ऐसी है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। हमारे देश में अक्सर 60-70 प्रतिशत मतदान होता है, यानी चुनी गई सरकार को 30 प्रतिशत जनता ने वोट नहीं दिया। जिन लोगों ने मतदान किया उनमें से भी बहुत से लोग विपक्षी अथवा स्वतंत्र उम्मीदवारों को वोट देते हैं। विजयी उम्मीदवार सिर्फ इसलिए चुन लिया जाता है क्योंकि उसे सबसे ज्यादा वोट मिले। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि कोई उम्मीदवार सिर्फ एक वोट के अंतर से जीता। यानी, जिन लोगों ने विजयी उम्मीदवार के खिलाफ वोट दिया, उनके वोट बेकार चले गए क्योंकि उनके मनपसंद का उम्मीदवार विधायक नहीं बन पाया। इस प्रकार सिर्फ एक वोट ज्यादा पाने वाला व्यक्ति सभी शक्तियों का स्वामी बन जाता है और हारा हुआ उम्मीदवार एकदम अप्रासंगिक हो जाता है। परिणाम यह है कि चुनाव जीतना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए उम्मीदवार जीत सुनिश्चित करने के लिए हर तरह के जायज़ और नाजायज़ तरीके अपनाते हैं। स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए शुरुआत हमें जड़ से करनी होगी, यानी चुनाव प्रणाली ऐसी बनानी होगी कि भ्रष्ट तरीकों से चुनाव जीतना संभव न हो सके। भारतीय आदतन भ्रष्ट नहीं हैं, हमारा सिस्टम हमें भ्रष्ट बनने के लिए विवश कर रहा है। उपाय यही है कि हम सिस्टम को मजबूत बनाएं, भ्रष्टाचार की संभावना पर रोक लगाने के उपाय करें ताकि समाज में चल रहे नैतिक पतन पर रोकथाम लग सके और हम विकास के पायदान चढ़ते रह सकें।

संपादक की कलम से

पीएम के पिता का अपमान

क्या यही हमारी राजनीतिक संस्कृति है? क्या ऐसे ही लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकार पर हम गर्व से इतराते रहे हैं? क्या देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री का कोई सम्मान और राष्ट्र की गरिमा कुछ मायने रखती है अथवा नहीं? कांग्रेस बार-बार ऐसी शर्मसार हरकतें क्यों करती है? क्या पार्टी के बिखराव, उसकी लगातार घटती स्वीकार्यता और चुनावी पराजय की कुंठाओं से पनपी विक्षिप्त मनःस्थिति है, जो प्रधानमंत्री के लिए अभद्र शब्दों के इस्तेमाल को बाध्य करती रही है? शिकायत और नाराज़गी प्रधानमंत्री की सरकारी नीतियों और उनके फैसलों से हो सकती है, प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता का अपमान करके कांग्रेस को क्या हासिल हो सकता है? कौन-सा मानसिक सुकून मिल सकता है? क्या देश की जनता यह सब कुछ नहीं देख रही, क्योंकि वह भी देश के प्रधानमंत्री के बार-बार अपमान से आहत होती है? प्रधानमंत्री तो कांग्रेस के लिए भी वही हैं, जो भारत देश का प्रथम लोकतांत्रिक और कार्यकारी चेहरा हैं। क्या ऐसे अभद्र और अपमानजनक शब्द बोलने वालों पर कांग्रेस के भीतर कोई आचार-संहिता, अनुशासन और नियंत्रण है अथवा वह भी 'शून्य' है? सरोकार भारत की राष्ट्रीय छवि और प्रतिष्ठा का भी है। पार्टी का एक बौना-सा प्रवक्ता, प्रधानमंत्री के पिता के नाम पर, मज़ाक करने का दुस्साहस कैसे कर सकता है? क्या इस संदर्भ में कोई निश्चित विधान नहीं है? शायद यही लोकतंत्र होता है! कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक सार्वजनिक मंच पर प्रधानमंत्री का पूरा नाम इस तरह लिया-नरेंद्र गौतम दास मोदी।' प्रधानमंत्री के पिता का नाम है-दामोदर दास। देश और राजनीति इससे बखूबी परिचित हैं। विवादास्पद उद्योगपति गौतम अडानी का नाम प्रधानमंत्री के साथ जोड़ कर, उनका उपहास उड़ाने की, विकृत पैरोडी बनाई गई। पवन खेड़ा ने यह जानबूझ कर कहा, क्योंकि उनके चेहरे के भाव से स्पष्ट था। इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के करीबी संबंधों का राजनीतिक वृत्तांत बनाया जा रहा है, ताकि घपले और भ्रष्टाचार के सवाल प्रधानमंत्री पर भी उठाए जा सकें। मुद्दा और विमर्श कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी घोर आपत्ति यह है कि प्रधानमंत्री के दिवंगत माता-पिता के नाम की विकृत पैरोडी क्यों बनाई जाए? दरअसल कांग्रेस में पवन खेड़ा तो बहुत जूनियर चेहरा हैं, लेकिन मणिशंकर अय्यर, जयराम रमेश, सुबोधकांत सहाय, रेणुका चौधरी, शशि थरूर, प्रमोद तिवारी, गुलाम नबी आज़ाद (तब कांग्रेस में) और संजय निरूपम आदि से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष रहे सोनिया और राहुल गांधी सरीखे वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए गालीनुमा शब्दों का इस्तेमाल किया है।

मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने गुजरात चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री को 'रावण' करार दिया था। ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस के छुटभैया प्रवक्ता दलीलें देने लगते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी गांधी-नेहरू परिवार के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था और अब भी करते रहते हैं। यह आरोप अद्र्धसत्य भरा है। कुछ तंज प्रधानमंत्री कसते रहते हैं, लेकिन उन्होंने अभिधा शब्द-शक्ति में प्रत्यक्ष रूप से किसी को भी गाली नहीं दी। हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री को भी कुछ संयम बरतना चाहिए, लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस प्रतिशोध की राजनीति करना चाहती है? प्रधानमंत्री मोदी ने इस संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी शख्स के माता-पिता का अपमान कभी नहीं किया, यह हम अपने अनुभव के आधार पर दावा कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने तो प्रधानमंत्री की मौत के प्रकार तक गिना दिए कि कैसे उनको मारा जा सकता है! एक नेता ने तो 'बोटी-बोटी' कर देने तक का सार्वजनिक बयान दिया है।

24 फरवरी का इतिहास

24 फरवरी का दिन भी भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है, इस दिन कई ऐसी छोटी-बड़ी घटनाएं घटी, जो कि हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गई। इसी दिन शिवाजी ने मुगलों के कब्जे वाले सिंहगढ़ किले को जीता, इसके साथ ही 17 फरवरी के दिन से साल 2004 में फूलनदेवी हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त शमशेर सिंह राणा तिहाड़ जेल से फरार हो गया।

इसके साथ ही इस दिन के. चन्द्रशेखर राव समेत कई ऐसे दिग्गजों ने जन्म लिया, जिन्होंने दुनिया में आकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। वहीं दूसरी तरफ 24 फरवरी को जेम्स ब्रेड टेलर समेत कुछ मशहूर लोग इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। उनके बारे में हम आपको अपने इस लेख में नीचे बता रहे हैं।

जर्मनी ने 1370 में रुडाउ की लड़ाई में लिथुआनिया को हराया।
सिंहगढ़ क़िले को 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुग़लों से जीता।
औरंगज़ेब ने 1698 में जिंजी के क़िले पर कब्ज़ा कर लिया।
फ्रांस के ख़िलाफ़ प्रसिया ने 1813 में जंग का ऐलान किया।
स्वेज़ नहर से 1867 को पहला जहाज़ गुजरा।
सैन फ्रांसिस्को शहर में 1878 में पहली बार टेलीफोन एक्सचेंज खोला गया।
सन 1882 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पहला टेस्ट मैच खेला गया।
महात्मा गांधी जी ने 1915 में पहली बार शांतिनिकेतन का दौरा किया।
जिसमे दीनानाथ मंगेशकर ने तेजस्विनी की भूमिका अदा की तथा वीर वामनराव जोशी द्वारा लिखित रणदुंदुभी नाटक का 1927 में मुंबई में प्रयोग हुआ।
वायसराय निवास में लॉर्ड इरविन ने 1931 में गांधी जी का स्वागत किया।
अमेरिका की साप्ताहिक पत्रिका 'न्यूजवीक' प्रकाशित 1933 में हुयी।
1934 में पर्वतारोहण के दौरान बेल्जियम नरेश अल्बर्ट प्रथम की मौत हुई।
सोवियत संघ में 'वायस ऑफ़ अमेरिका' का प्रसारण 1947 में शुरू किया गया।
जर्मनी के हैम्बर्ग में 1962 में हुए तूफ़ान से लगभग 300 लोगों की मौत।
ब्रिटिश संसद ने 1972 में यूरोपीय समुदाय में शामिल होने का प्रस्ताव पारित किया।
मकाऊ ने 1976 में संविधान को अंगीकार किया।
चीन की सेना ने 1979 में वियतनाम पर हमला किया।
नीदरलैंड ने 1983 में संविधान को अंगीकार किया।
फूलनदेवी हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त शमशेर सिंह राणा 2004 को तिहाड़ जेल से फरार।
बांग्लादेश की लेखिका तसलीमा नसरीन ने 2005 में भारतीय नागरिकता की मांग की।
अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने 2007 में इराक से सैनिकों को वापस बुलाये जाने की घोषणा की।
अनिल अंबानी ग्रुप ने 2008 में रिलायंस पावर के सभी नान-प्रमोटर शेयर धारकों को मुफ़्त बोनस शेयर देने पर विचार करने की घोषणा की।

एक लाख से ज्यादा स्कूल में केवल 1 टीचर कैसे सुधरेगी भारत की शिक्षा व्यवस्था

केंद्र सरकार ने 2023-24 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 1.13 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए, जिससे स्कूलों और उच्च शिक्षा पर अनुमानित खर्च 2022-23 की तुलना में 8.3 फीसदी बढ़ गया है। लेकिन हाल ही में संसद में सवालों के जवाब में पता चला कि भारत में अभी भी शिक्षा का हाल ठीक नहीं है। अभी इसमें काफी सुधार की जरूरत है। छात्र-शिक्षक अनुपात और एक टीचर वाले स्कूलों की संख्या प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी के गंभीर मुद्दे की ओर इशारा करती हैं। इसके अलावा देशभर में एक ओर जहां डिजिटल इंडिया की बात हो रही है वहीं लाखों स्कूल अभी तक इंटरनेट कनेक्टिविटी से दूर हैं।

देश में सबसे खराब छात्र-शिक्षक अनुपात वाले राज्यों में सबसे बड़ी आबादी या हाई जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार छात्र-शिक्षक अनुपात के मामले में सबसे खराब स्थिति में हैं। ये न केवल देश में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य हैं, बल्कि सबसे गरीब राज्यों में भी हैं। इसके विपरीत कम आबादी वाले राज्यों में छात्र-शिक्षक अनुपात ठीक है। लेकिन कम छात्र-शिक्षक अनुपात के बावजूद, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर है।

भारत के लगभग 8 फीसदी स्कूलों में केवल एक शिक्षक है। ज्यादा आबादी वाले राज्यों में भी एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या कम नहीं है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात 25 है। ये आरटीई एक्ट द्वारा अनिवार्य स्तर से बेहतर जरूर है, लेकिन इसी राज्य में सबसे ज्यादा एक टीटर वाले स्कूल हैं। बड़े राज्यों में केरल में 310 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक हैं। शिक्षा को डिजिटाइज करने पर जोर देने के बावजूद भारत में चार में से एक से भी कम स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी कार्यक्रम और पिछले साल राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय कार्यक्रम की घोषणा की थी ताकि लर्निंग आउटकम में सुधार किया जा सके और महामारी से संबंधित लर्निंग की भरपाई की जा सके। लेकिन 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में, आधे से भी कम स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है, जो इस तरह के डिजिटल कार्यक्रमों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।

मुफ्त की योजनाएं केवल गरीबों के लिए हों

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही कह चुके हैं कि प्रदेश की माली हालत बहुत ही खराब है और इसे पटरी पर लाने में कम से कम चार वर्ष का समय लगेगा। यह एक बहुत अच्छी सोच है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए इतने तत्पर हैं। इससे पहले भी शांता कुमार की सरकार ने प्रदेश के अनावश्यक खर्चों को कम करके प्रदेश को सन् 1992 में कर्ज मुक्त कर दिया था। अब इस सरकार से उम्मीद है कि अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगा कर और मुफ्त की रेवडियां बंद करके केवल गरीबों की मदद करे और प्रदेश की माली हालत में सुधार लाए' चाहे कोई भी सरकार हो, उसे जन कल्याणकारी योजनाएं बनानी ही पड़ती हैं लेकिन मुफ्त की योजनाएं केवल गरीब लोगों के लिए ही होनी चाहिए क्योंकि यदि मुफ्त की योजनाएं सभी लोगों के लिए हों तो सरकार के खजाने पर भारी बोझ पड़ता है जिससे विकास के कार्य बाधित होते हैं। संपन्न वर्ग आर्थिक रूप से मजबूत होता है। उसे मुफ्त की रेवडियां बांटना कहां तक उचित है? इस समय हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है जिससे प्रदेश बिजली बोर्ड करोड़ों रुपए के घाटे में चल रहा है। 125 यूनिट बिजली मुफ्त में देने से पहले भी बिजली बोर्ड घाटे में चल रहा था, अब तो यह घाटा और भी बढ़ता जाएगा। कांग्रेस सरकार ने हिमाचल के सभी लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का वायदा किया है। यदि सरकार ऐसा करती है तो बिजली बोर्ड का संकट और भी बढ़ जाएगा। अतः वर्तमान सरकार को चाहिए कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त में न देकर 125 यूनिट बिजली मुफ्त में केवल गरीब और गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को ही देनी चाहिए, ताकि बिजली बोर्ड पर कम से कम बोझ पड़े। मुफ्त की बिजली देने के लिए सरकार को बोर्ड को धनराशि उपलब्ध करवानी पड़ती है जो कि सरकार के लिए बहुत मुश्किल काम है क्योंकि सरकार पर वैसे भी लगभग 75000 करोड़ रुपए का कर्ज है। कोई समय था जब प्रदेश सरकार बिजली बोर्ड से कर्ज लेती थी, लेकिन अब स्थिति ठीक इसके उल्ट है। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य के लिए यह कर्ज एक बहुत बड़ी राशि है। सरकार के पास आय के सीमित साधन हैं। इन साधनों से प्रदेश को जो आमदनी होती है उसका बहुत बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन और पेंशन देने में ही खर्च हो जाता है।

कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वायदा भी किया है। यदि यह सभी महिलाओं को दिया जाता है जैसे कि बहुत सारी महिलाओं ने मिलने वाली इस राशि की उम्मीद लगाई है, तो सरकार के खज़ाने पर पडने वाले बोझ को सहन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह राशि भी केवल गरीब और जरूरतमंद तथा गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को दी जाए। यह बात सही है कि चुनावों से पहले जब कोई पार्टी किसी भी प्रकार का जनता से वायदा करती है तो सत्ता में आने पर उसे पूरा करना उस सरकार का कत्तव्य बनता है, लेकिन इसके लिए प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी देखनी पड़ती है। यदि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक न हो तो सरकार को जनता से रूबरू होकर सारी स्थिति को सामने रखना चाहिए ताकि लोग पूरी बात को समझ सकें, क्योंकि कोई भी साधन संपन्न व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मेरे प्रदेश की आर्थिक हालत और खराब हो और उससे होने वाले नुकसान से विकास कार्य बाधित हों। वैसे भी हिमाचल प्रदेश के अधिकतर लोग पढ़े लिखे और समझदार हैं, वे तो प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए अपना योगदान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। वैसे भी हमारे देश भारत में आज भी करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं और करोड़ों लोगों को भरपेट भोजन तक नहीं मिलता। ऐसे लोग भी इस देश के नागरिक हैं, उन्हें भी सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। यह सब हमारे भाई बहन हैं। इनके लिए यदि कोई भी सरकार मुफ्त की योजनाएं लागू करती है तो यह सारे देश में समानता लाने का एक बहुत बढिया प्रयास है। हमारे देश में अमीरी और गरीबी के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। इसे पाटने का प्रयास करना ही होगा। किसी भी प्रजातांत्रिक देश में सभी लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान होनी ही चाहिए। जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है तो आर्थिक बदहाली में सभी लोगों को मुफ्त की रेवडियां बांटना बंद कर दिया जाए।

कचरे के डिब्बे में चयन आयोग

विवादों की दास्तान में अंततः कर्मचारी चयन आयोग का अस्तित्व खत्म हो गया। पच्चीस साल के अपने इतिहास में पहले अधीनस्थ सेवा बोर्ड और बाद में कर्मचारी चयन आयोग ने अगर कुछ बटोरा, तो यह अविश्वसनीयता, अनियमितता और लचर व्यवस्था ही थी जो आखिर में सूली पर चढ़ गई। तमाम अनियमितताओं और विवादित सफर की कहानी में सुक्खू सरकार द्वारा कर्मचारी चयन आयोग की प्रथा पर लिया गया साहसिक फैसला, वक्त की नजाकत को संबोधित करता है। विडंबना यह कि इसके ऊपर भी सियासत शुरू हो रही है, लेकिन प्रसन्न ऐसी महत्त्वाकांक्षा जरूर होगी जो कर्मचारी चयन की अब तक की प्रक्रियाओं और पद्धतियों में गुणात्मक सुधार लाने की गुंजाइश देखती है। कम से कम डेढ़ दर्जन मामलों में चयन आयोग की अनियमितताओं का वज्रपात जिन बेरोजगार युवाओं ने सहा है, उनसे पूछ कर नेता बयान दें कि उचित व अनुचित के राजनीतिक मुहावरे कब तक वास्तविक समस्या के निवारण से दूर करते रहेंगे। पेपर लीक होने की वजह से अभिशप्त हुआ माहौल पहले से ही चयन आयोग को आशंकित कर चुका है, तो कचरी व्यवस्था को ठिकाने लगाने और नए विकल्प पेश करने की आवश्यकता दिखाई दे रही थी। ऐसे में सुक्खू सरकार ने अपने सख्त फैसले से पूरी व्यवस्था को कड़ा संदेश दिया है। यह प्रश्न एक संस्थान को बचाने की पैरवी से कहीं अहम इसलिए है कि ऐसी परीक्षाओं में पारदर्शिता कैसे लाई जाए।

पहले ही पुलिस भर्ती परीक्षा ने हिमाचल के ताने बाने में कई सांप नाथ पाल रखे थे और इस तरह की खामियों में कमोबेश हर सरकार के दौर में कोताही बरती गई। जाहिर है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर अगर कोई नई पद्धति ईजाद होती है, तो शक के दायरे टूटेंगे और कई युवाओं के प्रयास को ईमानदार व्यवस्था का विश्वास हासिल होगा। संस्थान का परिचय अगर कर्मचारी चयन आयोग बन कर भी अविश्वास के गर्त में जाना रहा, तो ऐसी तमाम शाखाएं कचरे के डिब्बे में डाल देनी चाहिएं। ऐसे फैसलों की तासीर में सुक्खू सरकार ने पुनः अपना कद और कवायद पेश की है।

इसे हम व्यवस्था परिवर्तन की दृष्टि से देखें, तो कर्मचारी चयन आयोग के कई पाप सामने हैं। जहां अध्यक्षीय पारियों में लोग बदनाम हुए हों, वहां

संस्थान की बदनामी हर युवा की महत्त्वाकांक्षा में चीखती है। विपक्ष को हर फैसले की आलोचना का हक है, लेकिन ऐसे संस्थान का दर्द किसी बेरोजगार के सीने में समझना होगा। ऐसी पद्धतियों की गिरफ्त में कितने बच्चों के करियर तबाह हुए, यह आज तक के भर्ती विवादों की पपड़ी उतार कर देखना होगा। ऐसे में राज्य टेस्टिंग एजेंसी या अथारिटी की दिशा में बढ़ रही सरकार से अपेक्षा रहेगी कि इस बार मरहम ही नहीं, बल्कि ऐसा समाधान सामने आएगा जो वर्षों की कालिख को साफ करके कर्मचारी चयन परीक्षाओं को ईमानदारी के फलक पर नए अवतार में पेश करेगा। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि कांग्रेस की दस गारंटियों में रोजगार की पेशकश का सफर चयन प्रक्रिया की आशंकाओं को मिटाकर शुरू होने की गारंटी दे रहा है। हम यह मूल्यांकन नहीं कर सकते कि सरकार की गारंटियां कब और किस तरह सामने आ रही हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की हर गारंटी से सुक्खू सरकार के रिपोर्ट कार्ड की ईमानदारी का ब्योरा जरूर सामने आएगा। परीक्षा तो हर संस्थान की है और वहां घर कर गई लचर संस्कृति या व्यवस्था की है। कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने से एक ताजगी भरी उम्मीद उन आवेदनों में जगी है, जो वर्षों से बेरोजगारों को लुटा पिटा महसूस कराने की परीक्षा में कैद रहे। व्यवस्था परिवर्तन के नारे को चयन आयोग के नजदीक खड़ा करके मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने निर्णायक रुख अख्तियार किया है। यही उद्बोधन कल जब चिकित्सा, शिक्षा संस्थानों, जनसंपर्क के कार्यालयों तथा सार्वजनिक भूमिका के संस्थानों के बाहर पहरेदारी देगा, तो ऐसे अनेक फैसलों की मिट्टी पर सुक्खू सरकार की बुलंदी मापी जाएगी।

ब्रीफ न्यूज

टॉप ट्रेंडिंग में बना हुआ है फिनोलेक्स केबल्स का स्टॉक, आगे भी तेजी के दिख रहे संकेत

शेयर बाजार में कई स्टॉक आज टॉप ट्रेंडिंग में बने हुए हैं। ऐसा ही एक स्टॉक फिनोलेक्स केबल्स का है। तकनीकी चार्ट पर भी शेयर काफी मजबूत नजर आ रहा है। स्टॉक में आज 7 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया है। इस शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है।

नई दिल्ली: शेयर बाजार में अस्थिरता के बीच कई शेयर टॉप ट्रेंडिंग में बने हुए हैं। इन शेयरों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। ऐसा ही एक स्टॉक फिनोलेक्स केबल्स का है। फिनोलेक्स केबल्स (एनएसई कोड - फिनकैबल्स) के शेयर बाजार में मजबूत अस्थिरता के बावजूद लगभग 7% बढ़ गए हैं। फिनोलेक्स केबल्स के शेयर ने गुरुवार को 709 रुपये के 52-सप्ताह के हाई लेवल को छुआ है। तकनीकी रूप से भी स्टॉक में मजबूती देखने को मिल रही है। इस स्टॉक ने अपने 63-सप्ताह के कप और हैंडल पैटर्न से भारी मात्रा में ब्रेकआउट दर्ज किया। छोटी अवधि में, स्टॉक अपने 5-दिवसीय लेवल से टूट गया है। तकनीकी पैरामीटर सकारात्मक प्राइज पैटर्न को दिखा रहे हैं। इसने एडीएक्स (37.76) में एक मजबूत सकारात्मकता के साथ 14-दिन का आरएसआई (76.20) तेजी के सेक्टर में है। OBV भी निवेशकों के बीच बढ़ती खरीदारी की रुचि को दर्शाता है। व्यापक बाजार के मुकाबले रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी शानदार है। यह उन कुछ शेयरों में से एक है, जिन्होंने बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद मजबूत खरीदारी गतिविधि का प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर, तकनीकी सेटअप में तेजी है और आने वाले समय में स्टॉक के और उच्च स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। निवेशक आने वाले कारोबारी सत्र के लिए इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं।

लॉजिस्टिक सेक्टर के इस शेयर ने निवेशकों को किया मालामाल, दो साल मे दिया 150 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न

शेयर बाजार में भले ही गिरावट हो लेकिन कई शेयरों ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। ऐसा ही एक स्टॉक लॉजिस्टिक सेक्टर की कंपनी ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स का है। इस शेयर ने निवेशकों को पिछले दो वर्षों में 150 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इस कंपनी में निवेश करने वाले मालामाल हो गए हैं।

मुंबई: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच लॉजिस्टिक सेक्टर की एक कंपनी ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। इस शेयर में लगातार तेजी बनी हुई है। यह शेयर ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड का है। ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स के शेयर 16 फरवरी 2021 को 130.4 रुपये के स्तर पर थे। यह शेयर बढ़कर 20 फरवरी 2023 को 363.95 रुपये के स्तर पर पहुंच गए थे। इस तरह से देखें तो पिछले दो साल की होल्डिंग अवधि में इस शेयर में 178% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। कंपनी S&P BSE स्मॉलकैप इंडेक्स का हिस्सा है। पिछले दो वर्षों में इस शेयर ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। अगर किसी ने दो साल पहले इस कंपनी के शेयरों में एक लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज उसे 2.79 लाख रुपये मिलते। Q3FY23 में कंपनी का शुद्ध राजस्व 26.80% और YoY घटकर 4099 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी मौजूदा समय में 27.70x के इंडस्ट्री पीई के मुकाबले 10.17x के टीटीएम पीई पर कारोबार कर रही है। कंपनी ने FY22 में 28.4% और 32.4% का ROCE और ROE हासिल किया है।

इन गर्मियों में बिजली का झटका सहने को रहिए तैयार, चार गुना बढ़ सकता है बिजली का बिल!

इस बार गर्मियों में बिजली का बिल आपको जोर का झटका दे सकता है। इसी वजह यह है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली बनाने वाली कंपनियों को एनर्जी एक्सचेंजेज पर महंगी बिजली बेचने की अनुमति दे दी है। अभी ऊर्जा बाजार में अगले दिन की खरीद के लिए कीमत की सीमा 12 रुपये प्रति यूनिट है।

नई दिल्ली: इस बार गर्मियों में आपका बिजली का बिल कई गुना बढ़ सकता है। इसकी वजह यह है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (CERC) बिजली जेनरेट करने वाली कंपनियों (Gencos) को एनर्जी एक्सचेंजेज पर महंगी बिजली बेचने की अनुमति दे दी है। इस समय ऊर्जा बाजार में अगले दिन की खरीद (Day Ahead Market) में 12 रुपये प्रति यूनिट की कीमत सीमा है। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है। राज्य सरकारों को कोटे की और पावर परचेज एग्रीमेंट की बिजली मिलती है। डिमांड ज्यादा होने पर डिस्कॉम कंपनियां एनर्जी एक्सचेंज से बिजली खरीदती हैं। अब उन्हें चार गुना कीमत पर बिजली खरीदनी पड़ेगी। जाहिर है कि वे इसका बोझ उपभोक्ताओं पर डालेंगे। इससे उपभोक्ताओं का बिल बढ़ना लाजमी है।

सीईआरसी ने ईंधन खर्च और अन्य शुल्कों के रूप में अधिक लागत वाली बिजली उत्पादन कंपनियां को एनर्जी एक्सचेंजेज में महंगी बिजली बेच की अनुमति दी है। ये कंपनियां प्रति यूनिट 50 रुपये तक कीमत ले सकेंगी। सीईआरसी तीन श्रेणी के जेनकोस को मानदंडों में छूट देगा। इनमें महंगे प्राकृतिक गैस (RLNG), आयातित कोयले और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) का इस्तेमाल करके संयंत्र चलाने वाले जेनकोस शामिल हैं। इस समय ऊर्जा बाजार में अगले दिन की खरीद में 12 रुपये प्रति यूनिट की कीमत सीमा है। इस सीमा के चलते अधिक लागत वाले जेनकोस आमतौर पर ऊर्जा एक्सचेंजों पर बिजली बेचने के इच्छुक नहीं होते हैं। इसके चलते उनकी बिजली उत्पादन क्षमता रुक जाती है।

कितनी रहेगी बिजली की डिमांड

सीईआरसी ने आगामी गर्मी के मौसम में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा एक्सचेंजों पर एक नया खंड शुरू करने की अनुमति दी है। इसे उच्च कीमत पर अगले दिन की खरीद (HP-DAM) नाम दिया गया है। इस खंड में 50 रुपये प्रति यूनिट तक की अधिकतम कीमत पर बिजली बेची और खरीदी जा सकती है। सीईआरसी ने इंडिया एनर्जी एक्सचेंज (Indian Energy Exchange) की याचिका पर यह ऑर्डर दिया है। इस साल अप्रैल में बिजली की मांग 230 गीगावाट पहुंचने का अनुमान है। पावर मिनिस्ट्री ने 15 इम्पोर्टेड कोल बेस्ट प्लांट्स को 16 मार्च से 15 जून तक फुल कैपेसिटी के साथ काम करने को कहा है ताकि गर्मियों के दौरान बिजली की मांग को पूरा किया जा सके।

फरवरी में ही अप्रैल का अहसास, अभी से सजने लगे हैं एसी के बाजार

इस साल समय से पहले गर्मी का अहसास शुरू हो गया है। इसे देखते हुए एयर कंडीशनर और कूलर का बाजार अभी से सजने लगा है। इसके डीलर और रिटेलर अभी से स्टॉक भरने लगे हैं। ग्राहकों ने भी दुकानों से पूछताछ शुरू कर दी है।

नई दिल्ली: यह साल मौसम के हिसाब से कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तो जनवरी की शुरूआत में भी पूस जैसा चिल्ला जाड़ा पड़ा। दूसरी ओर फरवरी में ही तापमान इतना बढ़ा कि अप्रैल का अहसास होने लगा। इसका असर एयर कंडीशन (Air Conditioner) या एसी (AC) के बाजार पर दिखने लगा है। आम वर्षों में फरवरी महीने में एसी का बाजार बिल्कुल ठंडा रहता था। लेकिन इस साल दिल्ली और आस पास के इलाकों में अभी से ही एसी और कूलर वाले दूकान में माल भरने लगे हैं।

अगले तीन महीने के लिए जुटाने लगे हैं सामान

पिछले साल कोरोना के दौरान चीन से आने वाले सामान की सप्लाई बाधित रही। इसलिए कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स बाजार में खूब आपाधापी रही। इसलिए इस साल इस क्षेत्र की कंपनियों ने अगले तीन महीने की मांग का आकलन करते हुए कलपुर्जों को जुटाना शुरू कर दिया है। उधर स्टॉकिस्ट और रिटेलर भी अपनी दुकान में स्टॉक जुटाना शुरू कर दिया है। छतरपुर में एसी मैन्युफेक्चरिंग कंपनी चलाने वाले अमित कुमार बताते हैं कि इस बार सब कुछ जल्दी शुरू हो गया। दुकानदारों ने फरवरी में ही माल भरना शुरू कर दिया तो ग्राहकों ने भी अभी से ही पूछताछ शुरू कर दी।

इस साल रहेगा हाई डिमांड

अमित कुमार का कहना है कि बीती सर्दी में जैसे खूब जाड़ा पड़ा, वैसे ही इस बार गर्मी भी खूब पड़ने के आसार हैं। इसलिए साल 2023 में एसी का बाजार हाई डिमांड में रहेगा। कंपनियों में एसी की प्रोडक्शन दिसंबर से शुरू हो जाती है, जो कि मार्च तक चलती है। इसके बाद होलसेल से लेकर रिटेल मार्केट में एसी की बिक्री जुलाई तक चलती है। इस साल सब कुछ जल्द ही शुरू हो गया है।

एसी के दाम बढ़ने के आसार नहीं

उनका कहना है कि एसी का कंप्रेसर और कॉपर के पार्ट पुर्जे चीन से आते हैं। बांकी सामान यहीं बनता है। इस साल कंपनियों के पास इन सामानों का पर्याप्त स्टॉक है। इसलिए एसी के रेट्स में बढ़ोतरी की गुंजाइश कम दिखती है। एसी में यूज होने वाले कॉपर के रेट इंटरनैशनल मार्केट पर निर्भर होते हैं। इसके ऊपर-नीचे होने का असर एसी के प्राइस पर पड़ता है। पिछले साल की तुलना में इस साल लंदन मेटर एक्सचेंज में कॉपर का भाव 1,000 रुपये कम है। इसका लाभ ग्राहकों को मिलेगा।

इन दिनों में अच्छी सर्विस मुहैया करा सकती हैं कंपनी और डीलर

गर्मियां शुरू हो गई हैं। दिन में पंखे चलने लगे हैं। रात में रजाइयों का इस्तेमाल बंद हो गया है। एसी का मार्केट तापमान पर निर्भर करता है। अभी से बाजार में ग्राहक आने शुरू हो गए हैं। ऐसी फैमली या उपभोक्ता जिन्हें इस साल एयर कंडीश्नर खरीदना है, वो मार्केट में आ रहे हैं। इन दिनों में कंपनी और डीलर अच्छी सर्विस मुहैया करा सकता है। क्योंकि, कस्टमर्स का प्रेशर कम होता है। टेक्नीकल टीम में कम समय में यूजर्स तक पहुंच जाती है। कंपनियां हर महीने एसी का रेट रिवाइस करती हैं। कंपनियों ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। मार्केट ग्रोथ का अंदाजा लगाकर इंडस्ट्री पिछले साल की तुलना में 20 से 25 प्रतिशत अधिक इन्वेंट्री बनाए रखेगा। रिटेल मार्केट में मार्च और अप्रैल में एसी की अच्छी सेल देखने को मिल सकती है।

अप्रैल से जोर पकड़ेगी डिमांड

बक्शी टेलीविजन कंपनी पहाड़गंज के गगन बक्शी का कहना है कि इस साल एसी की डिमांड अप्रैल में ही जोर पकड़ लेगी। पहले ऐसा मई या जून में होता था। इसका मुख्य कारण समय से पहले पारा चढ़न है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इसी महीने से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले सामानों की मांग बढ़नी शुरू हो गई है। आगे भी इसमें बढ़ोतरी ही होगी।

20 बार फेल होने के बाद खड़ी की 500 करोड़ की कंपनी, अब सिखाएंगे बिजनस के गुर, कौन हैं शार्क टैंक के नए जज विकास डी नाहर

शार्क टैंक इंडिया में नए जज विकास डी नाहर की एंट्री होने वाली है। विकास शो का हिस्सा बनने वाले हैं। हैपिलो के सीईओ विकास अब एंटरप्रेन्योर की किस्मत बदलने के लिए उन्हें कारोबार के गुर सिखाएंगे। आज की तारीख में उनकी कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ के करीब पहुंच गया है।

नई दिल्ली: बिजनस रियलिटी टीवी शो शार्क टैंक इंडिया (Shark Tank India Season 2) में नए शार्क की इंट्री होने वाली है। एंटरप्रेन्योर की किस्मत बदलने वाले इस शो में बिजनस जगत के दिग्गज शार्क्स के तौर पर शामिल हैं। शो में बोट (Boat) के सीएमओ और को-फाउंडर अमन गुप्ता, लेंसकार्ट (Lenskart) के फाउंडर पीयूष बंसल, शुगर कॉस्मेटिक की सीईओ विनीता सिंह (Vineeta Singh), कार देखो डॉट कॉम (Cardekho.com) के सीईओ अमित जैन, Emcure फर्मा नमिता थापर (Namita Thapar) और शादी डॉट कॉम (Shadi.com) के फाउंडर अनुपम मित्तल है। अब शो में नए शार्क की इंट्री होने वाली है। हैपिलो (Happilo) के फाउंडर विकास डी नाहर (Vikas D Nahar) शार्क टैंक इंडिया सीजन का हिस्सा बनने वाले हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में...

बार-बार फेल होने के बाद मिला सक्सेस

हैपिलो के को फाउंडर विकास डी नाहर शार्क टैक्स इंडिया सीजन 2 के गेस्ट शार्क के तौर पर शामिल हो रहे हैं। उन्होंने अपने इंट्रो वीडियो में बताया कि कैसे बार-बार फेल होने के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नाहर की कंपनी हैपिलो पष्टिक स्नैक्स खासतौर पर ड्राईफ्रूट बनाती है। कंपनी ने बहुत तेजी से ग्रोथ हासिल की। आज की तारीख में उनकी कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ के करीब पहुंच गया है। हालांकि .ये सफलता उन्हें आसानी से नहीं मिली। कंपनी को इस मुकाम पर पहुंचाने वाले नाहर से 20 बार असफलता का दर्द झेला है। नाहर कहते हैं कि मैंने बार-बार कोशिश की और यहीं मेरी सफलता का राज है। नाहर ने हैपिलो कंपनी की शुरुआत मात्र 10 हजार रुपये से की थी। उनकी कंपनी में सिर्फ दो लोग थे। आज ये कंपनी 500 करोड़ रुपये की है। देश के छोटे-बड़े स्टोर में, ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हैपिलो के प्रोडक्ट आपको आसानी से दिख जाएंगे।

कौन हैं विकास डी नाहर

विकास डी नाहर किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने बेंगलुरू यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। उन्होंने जैन ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। काम के साथ-साथ उन्होंने MBA किया। इसके साथ ही उन्होंने फूड इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। साल 2016 में उन्होंने हेल्दी स्नैक्स प्रोडक्ट के साथ हैपिलो की शुरुआत की। 40 वैरिइटी के ड्राई फ्रूट्स, 100 वैरिइटी के चॉकलेट, 60 वैरिइटी के मलासों के साथ उनकी कंपनी आज की तारीख में 500 करोड़ की बन चुकी है।

अंबानी के मुकाबले आधे पर आ गए अडानी, स्वाहा हुए 64,45,52,39,00,00 रुपये, अब बची इतनी नेटवर्थ

गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के लिए साल 2023 अच्छा नहीं जा रहा है। दोनों की नेटवर्थ में गिरावट आई है। लेकिन दौलत गंवाने के मामले में गौतम अडानी पहले नंबर पर हैं। गौतम अडानी की नेटवर्थ लगातार कम हो रही है। कभी अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहने वाले अडानी आज 29वें नंबर पर फिसल गए हैं।

नई दिल्ली: कभी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर चमकने वाले गौतम अडानी (Gautam Adani) आज टॉप 20 से भी बाहर हो चुके हैं। अमेरिकी रिसर्च फर्म की रिपोर्ट जब से आई है गौतम अडानी की नेटवर्थ लगातार कम होती जा रही है। गौतम अडानी (Gautam Adani) के शेयरों में भारी गिरावट देखी जा रही है। वह हर रोज अरबों रुपयों की दौलत गंवा रहे हैं। शेयरों में गिरावट के बीच अडानी अब दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 29वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। दौलत गंवाने के मामले में साल 2023 में गौतम अडानी पहले नंबर पर बने हुए हैं। एक समय ऐसा था जब गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर बनने से बस कुछ ही कदम पीछे थे। 24 जनवरी 2023 को अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से सबकुछ बदल गया। हर दिन अरबों रुपये की दौलत कमा रहे गौतम अडानी तेजी से नीचे लुढ़कने लगे। पहले वह अमीरों की लिस्ट में टॉप 10 से बाहर हुए। इसके बाद टॉप 20 से भी बाहर हो गए। अब वह 30वें स्थान पर लुढ़कने के करीब हैं। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) ने भी दौलत गंवाई है। लेकिन वह अभी भी टॉप 20 में बने हुए हैं। अब मुकेश अंबानी की नेटवर्थ गौतम अडानी से दोगुना ज्यादा हो गई है।

मुकेश अंबानी की तुलना में 14 गुना गंवाई दौलत

गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी की तुलना में 14 गुना दौलत गंवाई है। साल 2023 अडानी और अंबानी दोनों के लिए ही अच्छा नहीं रहा है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी इस साल दौलत गंवाने के मामले में सबसे आगे रहे हैं। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक, इस साल गौतम अडानी ने 77 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति गंवाई है। वह दौलत गंवाने के मामले में पहले नंबर पर हैं। वहीं अगर मुकेश अंबानी की बात करें तो उन्होंने 5.65 अरब डॉलर गंवाए हैं। मुकेश अंबानी के पास अभी 81.5 अरब डॉलर की दौलत है। वहीं गौतम अडानी की नेटवर्थ अब 42.7 अरब डॉलर रह गई है। अगर देखें तो मुकेश अंबानी के पास गौतम अडानी की तुलना में दोगुनी संपत्ति है।

शेयरों में आ रही गिरावट

अडानी ग्रुप के शेयरों में आज भी गिरावट देखी जा रही है। अडानी ग्रुप के ज्यादातर स्टॉक्स आज भी लाल निशान पर दिख रहे हैं। बुधवार को भी अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट की वजह से गौतम अडानी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

अडानी के शेयरों को छोड़िए! इन सस्ते शेयरों ने सिर्फ 6 महीने में दोगुना कर दिया पैसा

शेयर बाजार में कई निवेशकों को शानदार रिटर्न मिला है। स्टॉक्स मार्केट में कई शेयर ऐसे हैं जिन्होंने पिछले छह महीनों में ही निवेशकों को दोगुना तक रिटर्न दे दिया है। इन शेयरों में अभी भी तेजी बनी हुई है। निवेशकों को उम्मीद है कि आने वाले समय में इन शेयरों में और तेजी देखने को मिल सकती है।

नई दिल्ली: शेयर बाजार (Stock Market) में अगर मुनाफा कमाना हो तो सही समय पर सही स्टॉक्स में पैसा लगाना जरूरी है। बाजार (Stock Market) में भले ही गिरावट हो लेकिन बहुत से शेयर ऐसे हैं जिन्होंने निवेशकों का पैसा दोगुना तक कर दिया है। इन शेयरों ने बेहद कम समय में निवेशकों को मालामाल बना दिया है। अभी भी इन शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। निवेशकों को उम्मीद है कि आने वाले समय में इन शेयरों में और शानदार रिटर्न मिल सकता है। आज हम आपको ऐसे ही शेयरों (Multibagger Stocks) के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ 6 महीनों में निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है। निवेशकों को बंपर रिटर्न मिला है। ये सभी स्टॉक्स (Multibagger Stocks) सस्ते हैं। मुनाफा कमाने के लिए आप इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। हालांकि आप किसी भी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहाकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है।

इन शेयरों ने 6 महीने में दोगुना कर दिया निवेश

पिछले छह महीनों में निवेशकों को मालामाल करने वाला पहला स्टॉक यूको बैंक (UCO Bank Share) का है। इस शेयर ने पिछले छह महीनों में निवेशकों को 116 फीसदी से ज्यादा का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। यह शेयर छह महीने पहले बीएसई पर 11 रुपये का था। वहीं मौजूदा समय में यह शेयर 25.30 रुपये के स्तर पर बना हुआ है। कोलकाता स्थित यूको बैंक ने दिसंबर तिमाही के दौरान करीब 653 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया है।

8 रुपये का शेयर पहुंचा 16 रुपये के पार

निवेशकों को मालामाल करने वाला दूसरा शेयर साउथ इंडियन बैंक (South Indian Bank Limited Share) का है। यह शेयर छह महीने पहले 7.90 रुपये के स्तर पर था। वहीं आज यानी 23 फरवरी 2023 को शेयर का भाव 16.90 रुपये तक हो चुका है। शेयर में अभी भी तेजी बनी हुई है। पिछले छह महीनों में इसने निवेशकों को 115 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। दिसंबर तिमाही में प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक का मुनाफा 102.7 करोड़ रुपये था। हालांकि सितंबर तिमाही में बैंक ने 223 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हासिल किया था।

बेबाक, दो टूक, टू द पॉइंट...दुनिया के मंच पर न्यू इंडिया की बुलंद आवाज हैं एस जयशंकर

एस.ठी. सेठी

विदेश मंत्री एस. जयशंकर का अपना अंदाज है। वह अंतरराष्ट्रीय मसलों पर अपनी बेबाक, दो टूक और टू द पॉइंट बात के लिए जाने जाते हैं। एएनआई को दिए अपने हालिया इंटरव्यू में जयशंकर ने चीन के साथ तनाव और एलएसी के हालात पर भी अपनी बात रखी।

नई दिल्ली : गए वो दिन जब पश्चिमी देश कथित मानवाधिकारों के नाम पर इंडिया पर लेक्चर दिया करते थे। धौंस दिखाया करते थे। आज का भारत पलटकर जवाब भी देता है। आईना भी दिखाता है। गए वो दिन जब अंतरराष्ट्रीय दबावों पर भारत बहुत सतर्क और नपा-तुला, संतुलित प्रतिक्रिया देता था। डिफेंसिव अप्रोच अपनाता था। न्यू इंडिया अब वैश्विक मंचों पर बेबाक, दो टूक और टू द पॉइंट बात रखता है। डंके की चोट पर। और न्यू इंडिया की सबसे बुलंद आवाज बनकर उभरे हैं विदेश मंत्री एस. जयशंकर।

'मैं चीन का नाम ले रहा हूं...', राहुल गांधी पर पलटवार

अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर अक्सर अपने बेबाक और दो टूक बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले जयशंकर फिलहाल अपने एक हालिया इंटरव्यू की वजह से चर्चाओं में हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में उनका एक कूटनीतिज्ञ के साथ-साथ एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ का रूप भी दिखा। विपक्ष के इस नैरेटिव कि 'मोदी सरकार चीन का नाम लेने से डरती है' की जयशंकर ने किसी मंझे हुए राजनेता की तरह हवा निकाल दी। उन्होंने कहा, 'चीन की सीमा पर आज हमारे पास इतिहास की सबसे बड़ी तैनाती है और मैं चीन का नाम ले रहा हूं। अगर हम रक्षात्मक हो रहे थे तो इंडियन आर्मी को एलएसी पर किसने भेजा? राहुल गांधी ने उन्हें नहीं भेजा, नरेंद्र मोदी ने भेजा।' एस जयशंकर ने कहा, 'आज चीन सीमा पर शांतिकाल में हमारे इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती है। हम अपने जवानों को तैनात किए हुए हैं। हमने अपनी सरकार के दौरान बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को 5 गुना बढ़ाया है। अब बताइए कौन रक्षात्मक है? कौन सच्ची बात कह रहा है? कौन सही-सही बता रहा है?'

'डिप्लोमैटिक' नहीं, दो टूक जवाब

एस. जयशंकर ज्वलंत मुद्दों पर 'डिप्लौमैटिक' जवाब नहीं देते। अपने यहां डिप्लोमैटिक का अर्थ ही गोल-मोल हुआ

करता था। वह सीधे मुद्दे की बात कहने के लिए जाने जाते हैं। अमेरिका या वहां की कोई संस्था जब मानवाधिकार, धार्मिक आजादी वगैरह के बहाने भारत पर सवाल खड़ी करती है तो जयशंकर को उनके ही मंच पर उन्हें आईना दिखाते हुए देखा जा चुका है। उन्हें रूस से तेल खरीद पर यूरोप के पाखंड की धज्जी उड़ाते दुनिया ने एक से ज्यादा कई मौकों पर देखा है। वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कई बार दो टूक कह चुके हैं कि भारत की विदेश नीति, उसके फैसले उसके और उसके लोगों के हितों के लिहाज से ही तय होंगे।

आतंकवाद पर पाकिस्तान को लगा चुके हैं लताड़

जब वह पाकिस्तान को 'आतंकवाद का केंद्र' (Epicentre of Terrorism) ठहराते हैं तो साथ में ये भी कहते हैं कि वह सीमा-पार आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान की भूमिका बताने के लिए 'इससे भी कड़े शब्दों' का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया में ZIB2 पॉडकास्ट को दिए इंटरव्यू में जयशंकर ने कहा, 'आप डिप्लोमैट हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सच नहीं बोलेंगे। मैं एपिसेंटर से भी तल्ख शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूं...हमारे साथ जो हो रहा है, उसे देखते हुए एपिसेंटर बहुत ही डिप्लोमैटिक शब्द है।' जयशंकर जब एलएसी पर तनाव और चीन के साथ संबंधों की बात करते हैं तो वह भी बिना लाग-लपेट के दो टूक होता है। एलएसी पर तनाव को हल्का करके दिखाने की चीन की कोशिश पर वह दो टूक कह चुके हैं कि सीमा पर हालात से ही द्विपक्षीय रिश्ते भी तय होंगे।

भारतीय विदेश नीति पर एस. जयशंकर की छाप

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बुलंद आवाज देश की बढ़ती हुई ताकत को भी दिखाता है। वैसे ये न्यू इंडिया रातों-रात नहीं खड़ा हुआ। हां, आज विदेश नीति पर एस जयशंकर की छाप है। केंद्रीय मंत्री बनने से पहले वह विदेश सेवा के तेजतर्रार अफसर थे। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और दांव-पेच के वह माहिर खिलाड़ी रह चुके हैं। वह एक राजनेता से इतर खांटी कूटनीतिज्ञ हैं जो अंतरराष्ट्रीय मसलों खासकर भारत से जुड़े मुद्दों पर काफी मुखर, स्पष्ट और बेबाक हैं।

अंदाज में आक्रामक जरूर मगर अभद्र नहीं

जयशंकर की मुखरता न्यू इंडिया की बुलंद आवाज है, न कि किसी विदेश मंत्री का बड़बोलापन। उनका अंदाज आक्रामक जरूर है मगर अभद्र नहीं। बड़बोला नेता अगले ही पल भीगी बिल्ली बना दिख सकता है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का ही उदाहरण देख लीजिए। दिसंबर 2021 में कुरैशी सऊदी अरब के विदेश मंत्री नवाफ बिन सैद अल मलकी के सामने अकड़ में बैठे...अशिष्ट अंदाज में। उनकी तरफ अपने जूते करके बैठे। हालांकि, खोखलेपन से भरी ये अकड़ और हेकड़ी जल्द ही निकल गई और पाकिस्तान को 'मदद' के लिए सऊदी का मान-मनुहार और चिरौरी करनी पड़ी और ये सिलसिला अब भी जारी है।

ताज महोत्सव में परफार्मेंस के दौरान मंच पर पहुंचा कुत्ता, जमकर हुई हूटिंग

एनटीवी न्यूज

आगरा में चल रहे ताज महोत्सव में परफार्मेंस के दौरान मंच पर कुत्ता पहुंच गया। मौजूद दर्शकों ने जमकर हूटिंग की। इस दौरान जिलाधिकारी भी दर्शकदीर्घा में मौजूद रहे।

आगरा: ताज महोत्सव में कार्यक्रम के दौरान एक कुत्ता अचानक मंच पर पहुंच गया। कुत्ते के आने से कार्यक्रम में व्यवधान आ गया। दर्शकदीर्घा में बैठे लोगों ने हूटिंग शुरू कर दी। आनन-फानन में कुत्ते को भगाया गया। मंच पर परफॉर्मेंस दे रहे कलाकारों को अपनी प्रस्तुति बीच में रोकनी पड़ी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यूपी टूरिज्म द्वारा आगरा में ताजमहोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। ताज महोत्सव 20 फरवरी से एक मार्च तक चलेगा। बुधवार रात करीब 10:30 बजे मंच पर सचेत टंडन और परंपरा का बॉलीवुड नाइट कार्यक्रम मुक्ताकाशीन मंच पर चल रहा था। इसी बीच एक कुत्ता पीछे से मंच पर चढ़ आया। कुत्ते के आ जाने से सचेत और परंपरा को अपनी प्रस्तुति रोकनी पड़ी। बताया जा रहा है कि उस दौरान जिलाधिकरी नवनीत चहल भी दर्शकदीर्घा में बैठे थे।

डीएम भी देखकर रहे गए हैरान

ताजमहोत्सव कार्यक्रम को लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही थीं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस और नगर निगम के कर्मचारी तैनात किए गए हैं, लेकिन मुक्ताकाशीय मंच पर कुत्ते के अचानक चढ़ जाने की घटना ने व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। मंच पर अचानक कुत्ते को देख जिलाधिकारी नवनीत चहल भी दंग रहे गए।

इनसाइड

जीतन राम मांझी की गरीब संपर्क यात्रा के पहले गया में अश्लील डांस का वीडियो वायरल, देखिए

गया: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इन दिनों गरीब संपर्क यात्रा पर हैं।नके साथ पुत्र और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन भी साथ चल रहे हैं। इसी दौरान गुरुवार को यह तस्वीर उनके गरीब संपर्क यात्रा के दौरान सामने आई है। गया-बोधगया सड़क मार्ग पर खिरियावां गांव के समीप सूरजपुरा हाट मैदान में गरीब संपर्क यात्रा की नुक्कड़ सभा आयोजित की गई थी। भीड़ को जुटाने के लिए यहां पर अश्लील डांस करवाया जा रहा था। इस मामले में जीतन राम मांझी की पार्टी से संबंधित कोई भी पदाधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। गौरतलब है कि जीतन राम मांझी की गरीब संपर्क यात्रा बिहार के नवादा जिले से शुरू हुई थी, जो इन दिनों गया जिले के विभिन्न जगहों पर चल रही है।

जी 20 वर्किंग ग्रुप ऑफ कल्चर की मीटिंग में संस्कृति की अहम भूमिका पर जोर, देखिए तस्वीरें

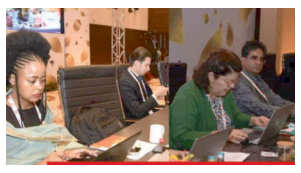

छतरपुर जिले में खजुराहो के महाराज छत्रसाल स्टेडियम में जी20 वर्किंग ग्रुप ऑफ कल्चर की पहली मीटिंग गुरुवार को हुई। इसे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार और केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने संबोधित किया। बैठक में अलग-अलग देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा कि संस्कृति राष्ट्रों और समुदायों के बीच टिकाऊ और इन्क्लूसिव ग्रोथ को आगे ले जाने का जरिया है। आर्थिक विकास, सामाजिक समरसता और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने में भी संस्कृति की भूमिका बहद महत्वपूर्ण है। अपने संबोधन में मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जी 20 कल्चर वर्किंग ग्रुप देशों के बीच एक सेतु का काम करता है। संस्कृति सबको जोड़ने का काम करती है और यह ग्रुप मानवता को सांस्कृतिक नजरिये से देखता है।

लेखी ने कहा कि मौजूदा दौर में लिंग समानता पर काफी जोर दिया जाता है। भारत में इसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हड़प्पाकालीन कांस्य की वह मूर्ति है जिसमें एक लड़की नृत्य करती हुई दिखती है। इस मूर्ति से पता चलता है कि हजारों साल पहले भी भारत में लिंग समानता की धारणा न केवल मौजूद थी, बल्कि महिला की देवी के रूप में पूजा भी की जाती थी।

लखनऊ समिट में नहीं दिखे अडानी, पर विपक्ष की सरकारें हिंडनबर्ग पर इतना खामोश क्यों हैं?

एनटीवी संवाददाता

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी का कारोबार हिल गया है। उनका नेटवर्थ घटने से रैंकिंग में वह फिसल रहे हैं। पिछले दिनों लखनऊ में हुए इन्वेस्टर समिट में अडानी नहीं दिखे तो कई तरह की बातें होने लगीं। लेकिन दिलचस्प यह है कि ममता बनर्जी, केरल के सीएम, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत समेत ज्यादातर विपक्ष शासित राज्य हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर खामोश क्यों हैं?

नई दिल्ली: पिछले आठ साल से भारत में होने वाली हर इन्वेस्टर समिट में गौतम अडानी (Gautam Adani) दिखाई देते रहे। देश के इस दिग्गज उद्योगपति को ही गांधीनगर में नरेंद्र मोदी के वाइब्रेंट गुजरात समिट का आर्किटेक्ट माना जाता है। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हालांकि अडानी खुद को लो-प्रोफाइल में ही रखते थे। वह दूसरी पंक्ति में बैठते जबकि मोदी के साथ आगे की पंक्ति में मुकेश अंबानी, रतन टाटा, आदि गोदरेज और डिप्लोमेट बैठे दिखते। दिल्ली आने से पहले वाइब्रेंट गुजरात की सफलता ने मोदी की छवि इंडस्ट्री-फ्रेंडली बनाने में मदद की। बाद के वर्षों में हर राज्य ने इंडस्ट्री को लुभाने के लिए गुजरात जैसी पहल शुरू की। मोदी को करीब से जानने समझने वाले बहुत से लोग मानते हैं कि वाइब्रेंट गुजरात एक ऐसा कदम था, जिससे उनके गांधीनगर से उड़कर दिल्ली पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हुआ। हमारे सहयोगी अखबार TOI में राधिका रमेशन पूरे घटनाक्रम पर विश्लेषण किया है। उन्होंने पूछा है कि आखिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर विपक्ष शासित राज्य चुप्पी क्यों साधे हुए हैं?

मोदी से अडानी की करीबी लेकिन...

वैसे, इन्वेस्टर इवेंट्स में अडानी पहले ही रॉक स्टार बन चुके थे लेकिन 2014 के बाद मोदी से निकटता दिखाई देने लगी। राजनीति और बिजनस के रिलेशन को आमतौर पर छिपाया जाता रहा या बात नहीं होती थी। हालांकि अडानी ने सभी दलों में दोस्त बनाए जिससे केवल मोदी के साथ जोड़कर उनकी पहचान न बने।अडानी ने कांग्रेस के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों कमलनाथ और विलासराव देशमुख के कार्यकाल में भी काम किया है। कुछ लोग उन्हें करीबी भी मानते हैं। हालांकि तमाम विवादों के बावजूद एक भी गैर-भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री ने हिंडनबर्ग धमाके के बाद चल रहे प्रोजेक्ट को रोकने की बात नहीं कही, जहां अडानी ने निवेश कर रखा है।

ममता भी हिंडनबर्ग पर खामोश

ध्यान रखना चाहिए कि ममता बनर्जी और पिनराई विजयन भी खामोश हैं। केवल

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगर विकास का पैमाना केवल अडानी हैं तो इस तरह का विकास नहीं चाहिए। सीएम ने कहा कि ऐसा विकास चाहिए जिसमें देश के किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, आदिवासी का विकास हो। केवल मुट्ठीभर लोगों का विकास नहीं चाहिए।

लखनऊ क्यों नहीं आए अडानी

हाल में लखनऊ में 10 से 12 फरवरी तक हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से अडानी दूर रहे। हालांकि इसकी उतनी चर्चा नहीं हुई। जबकि योगी सरकार ने निवेशकों को लुभाने के लिए 22 मंत्रियों और अधिकारियों को यूरोप भेजा था। RIL ने 75,000 करोड़ रुपये मुख्य रूप से 5जी सर्विस में निवेश करने की बात कही है। एन चंद्रशेखरन (टाटा ग्रुप) ने दावा किया यूपी 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने की ओर अग्रसर है। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने 25,000 करोड़ के निवेश की बात कही है। लेकिन लखनऊ में लोग हैरान रह गए कि अडानी को क्या हुआ और क्या उन्हें लखनऊ से दूर रहने को कहा गया था। अंदर ही अंदर मिस्टर-A की चर्चा होती रही।

योगी का सख्त फैसला

2022 में जब अडानी एशिया के सबसे अमीर शख्स थे, यूपी में 70,000 करोड़ के निवेश से 30,000 नौकरियों के सृजन की बात कही गई थी। तब अडानी ने यूपी में 24,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की थी, जो मुकेश अंबानी से एक तिहाई से भी कम थी। इस बार अडानी के मौजूद न होने से बातें होने लगीं जैसे उनके बुरे दिन आ गए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आने के बाद 4 फरवरी को योगी सरकार ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम को स्मार्ट पावर मीटर सप्लाई करने का अडानी ग्रुप का 5,400 करोड़ का टेंडर रद्द कर दिया। पावर कॉरपोरेशन कर्मचारी संघ मांग कर रहा था कि अडानी ग्रुप का टेंडर निरस्त किया जाए क्योंकि 6,000 रुपये का बेंचमार्क तय किया गया था और उनका कोटेशन 10,000 प्रति पावर मीटर काफी ज्यादा है।

माना जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के केंद्र के साथ कभी अच्छे संबंध नहीं रहे। मंत्रियों को शामिल करने का मामला हो या ब्यूरोक्रेट की नियुक्ति आदित्यनाथ खुद एक पावर सेंटर बनकर उभरे। दिल्ली-लखनऊ समीकरण की हमेशा बात की जाती रहती। ऐसे में यह सवाल उठा कि क्या अडानी का न होना योगी आदित्यनाथ का एक तरह का सिग्नल था? या क्या अडानी से खुद दूर रहने को कहा गया था? अटकलों पर अटकलें लगाई जा रही हैं।

अडानी आते तो क्या हो जाता?

यूपी के एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि अडानी का होना शायद एक मुद्दा बन सकता था। उद्योग के बड़े प्रतिनिधि आगे की पंक्ति में बैठे थे लेकिन क्या अडानी उनके साथ बैठते या क्या वे अपने बीच उन्हें पसंद करते? इसी तरह, फरवरी 2018 में लखनऊ में इन्वेस्टर समिट में मुलायम सिंह यादव, अमिताभ बच्चन और अनिल अंबानी के करीबी अमर सिंह वीवीआईपी के बीच जगह बनाने की उम्मीद कर रहे थे लेकिन मौका नहीं मिला था। इसे योगी की तरफ से सिंह के लिए एक संदेश के तौर पर देखा गया। हालांकि एक अधिकारी का कहना है कि अडानी का होना जरूरी नहीं था क्योंकि वह कुछ दिन पहले ही सीएम से मिले थे और उन्होंने बता दिया था कि वह क्या करेंगे। 2022 में अडानी को पीपीपी पार्टनरशिप के तहत छह लेन वाला गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट मिला। इसके लिए उन्हें एसबीआई से 10,238 करोड़ भी मिलेगा। यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा जो पश्चिम में मेरठ को अवध में प्रयागराज से जोड़ेगा।

राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बंगाल में भी अडानी हैं

पिछले साल अडानी ने कांग्रेस शासित राजस्थान में 65,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की थी। ग्रुप ने 2015 में छत्तीसगढ़ में रिफाइनरी और कई प्लांट शुरू किए, जब वहां भाजपा सरकार थी। कांग्रेस राज में भूपेश बघेल के कार्यकाल में राज्य सरकार की बिजली कंपनी ने कोरबा जिले में दो कोल ब्लॉकों को विकसित और संचालित करने के लिए अडानी ग्रुप को सिलेक्ट किया।

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जुलाई 2022 में बिजनस कॉन्क्लेव में अडानी का जमकर स्वागत किया। उन्होंने कहा, 'राजनीति अलग है और इंडस्ट्री बिल्कुल अलग है।' इधर, केरल सीएम ने विपक्ष के तीखे विरोध और दबाव के बावजूद विझिंगम पोर्ट के विकास का जिम्मा अडानी को दे दिया। अडानी उत्तर प्रदेश समिट से दूर क्यों रहे, यह रहस्य का विषय है जबकि दिलचस्प यह है कि विपक्ष शासित राज्य लगातार उन पर भरोसा कर रहे हैं।

संसद और दूसरी विधानसभाओं की तरह गुजरात विधानसभा के पास नहीं है ये सुविधा, 14 साल है पाबंदी

देश की तमाम विधानसभाओं ने अपने कार्यवाही को लाइव किया हुआ है। कोई भी देश-दुनिया के कोने में बैठकर भी अपने राज्य की विधानसभा की कार्यवाही को देख सकता है, यहां तक कि अब अदालतों की कार्यवाही भी लाइव हो गई है लेकिन गुजरात की विधानसभा में लाइव टेलीकास्ट की सुविधा नहीं है।

अहमदाबाद: संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कामकाज देखने की सुविधा सालों से है। सदन में निर्वाचित जनप्रतिनिधि कौन से मुद्दे उठा रहा हैं? इसको बताने और दिखाने के लिए देश की कई विधानसभाओं ने सदन की कार्यवाही को ऑनलाइन प्रसारित करना शुरू किया है। इसमें उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से लेकर दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, लेकिन गुजरात विधानसभा में जीवंत प्रसारण देखने की सुविधा नहीं है। 23 फरवरी को 15वीं गुजरात विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई, लेकिन आम नागरिक राज्यपाल देवव्रत के संबोधन से लेकर तमाम कार्यवाही को नहीं देख पाए। जानकारी के अनुसार 2009 तक गुजरात विधानसभा की कार्यवाही को लाइव देखने की सुविधा थी, लेकिन इसके बाद इसे बंद कर दिया

गया है। तब से लेकर अब गुजरात विधानसभा की कार्यवाही को लाइव करने की मांग लगातार उठ रही है। ऐसे में जब विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी की चुनाव हुआ है तो यह मांग फिर से उठनी शुरू हुई है कि विधानसभा की कार्यवाही लाइव होनी चाहिए, ताकि प्रदेश के लोग अपने जनप्रतिनिधियों के कामकाज को देख सकें। विधानसभा की कार्यवाही को लाइव करने मांग काफी समय से उठा रही है। सूरत के सामाजिक कार्यकर्ता ध्रुवित मनसुख ढोलरिया इसको लेकर कई बार विपक्ष से लेकर विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके है। ढोलरिया का कहना है कि विधानसभा की कार्यवाही लाइव होनी चाहिए। नेता अपने कार्यक्रम करते हैं तो फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया पर लाइव करते हैं। राज्य सरकार के कार्यक्रम भी सोशल मीडिया पर लाइव होते हैं। तो ऐसा सरकार को क्या डर है कि विधानसभा की कार्यवाही लाइव नहीं कर रही है। विधानसभा की कार्यवाही को देखना जनता का अधिकार है।

हाईकोर्ट पहुंच चुका मामला

जनवरी, 2021 में गुजरात विधानसभा की कार्यवाही को लाइव करने और दस्तावेजों को ऑनलाइन मुहैया कराने को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा सचिवालय से जवाब मांगा था तो विधानसभा ने सदन की सीधे प्रसारण की मांग विरोध किया था। सचिवालय ने तब तर्क दिया था कि कौन सी जानकारी प्रकाशित करने के लिहाज से ठीक है। इसका फैसला करने का अधिकार विधानसभा का है।

27 साल से बीजेपी की सत्ता

गुजरात में पिछले 27 सालों बीजेपी सत्ता पर काबिज है। 2022 के चुनावों की बात करें तो बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी। बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर 156 सीटें कब्जा ली थीं तो वहीं कांग्रेस 17, आप 5 पर सिमट गए थे। तीन सीट निर्दलीय और एक सीट पर समाजवादी पार्टी से लड़े प्रत्याशी को जीत हासिल हुई थी। ऐसे में जब बीजेपी प्रचंड बहुमत से लौटी हैं तो विधानसभा की कार्यवाही को लाइव करने की मांग फिर से जोर पकड़ रही है।